पेज 06

IPL 2027 में नहीं दिखेंगे 3 दिग्गज क्रिकेटर

साप्ताहिक

शहर सत्ता

PRGI NO. CTHIN/25/A2378

सोमवार, 31 अगस्त से 06 सितंबर 2026

हम दिखाएंगे आईना...

पेज 07

छत्तीसगढ़ में 3 साल बाद एक मंच पर खेल सम्मान

वर्ष : 02 अंक : 26 पृष्ठ : 08 मूल्य : 5 रुपए www.shaharsatta.com

पेज 04 खुरचन : डिवाइडर पर लोकतंत्र की नई पौध

सुशासन का मूल मंत्र महिलाओं का सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण

बहनी, दीदी, महतारी, सियान के दुलरवा हे हमर 'बिस्नु'

मुख्य संवाददाता/प्रदीप चंद्रवंशी
मोबाईल नंबर 7000681023

घर को मंदिर बनाने की महती जिम्मेदारी हमारी माँ, बहनों की है और उनके सम्मान, स्वाभिमान के साथ उनकी सुरक्षा का जिम्मा घर के मुखिया का होता है। छत्तीसगढ़ की समृद्धि और मजबूत आधारशिला मुख्यमंत्री विष्णु देव सहाय हैं। राज्य निर्माण से लेकर अब तक सभी मुख्यमंत्रियों में से एकमात्र विष्णु सरकार ने ही सुशासन का मूल मंत्र महिलाओं का सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण निर्धारित किया है। नतीजा साफ है अब बहनी, दीदी, महतारी अउ सियान के दुलरवा हे हमर 'विस्नु'...

महिला सशक्तिकरण के पांच स्तंभ

1. आत्मसम्मान और निर्णय लेने स्वतंत्रता — महिलाओं को अपने जीवन से जुड़े फैसले स्वयं लेने की स्वतंत्रता और आत्मसम्मान का अधिकार।

2. शैक्षिक सशक्तिकरण — महिलाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास सुनिश्चित करना, जिससे वे अपने अधिकारों को समझ सकें और आत्मनिर्भर बन सकें।

3. आर्थिक सशक्तिकरण — महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता, समान वेतन, रोजगार के अवसर और आर्थिक संसाधनों तक पहुंच प्रदान करना।

4. सामाजिक सशक्तिकरण — समाज और परिवार में महिलाओं को समान सम्मान देना तथा भेदभाव, दहेज प्रथा व बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं का अंत करना।

5. राजनीतिक प्रतिनिधित्व — राजनीति, नीति-निर्माण और नेतृत्व के पदों पर महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना।

प्रमुख योजनाएं

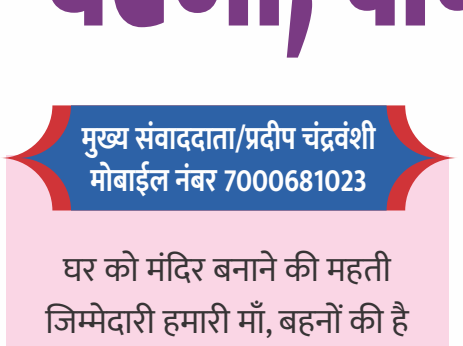

महतारी वंदन योजना — इसके तहत पात्र विवाहित महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये की सीधी आर्थिक सहायता (DBT) दी जाती है। इसका उद्देश्य महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन और पोषण स्तर सुधारना है।

नोनी सुरक्षा योजना — बालिकाओं के भविष्य, शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य को सुरक्षित करने के लिए यह योजना चलाई जा रही है।

छत्तीसगढ़ महिला कोष — महिला स्व-सहायता समूहों और महिलाओं को स्वरोजगार के लिए कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

लखपति दीदी पहल — स्व-सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का काम किया जा रहा है।

आर्थिक स्वतंत्रता और वित्तीय समावेशन

सूक्ष्म ऋण और बचत — ये समुह महिलाओं में बचत करने की आदत डालते हैं और उन्हें बिना किसी कठिन प्रक्रिया के आसानी से सूक्ष्म ऋण (micro-credit) उपलब्ध कराते हैं।

साहूकारों से मुक्ति — महिलाएं महंगे ब्याज वाले स्थानीय साहूकारों के चंगुल से बाहर निकलती हैं।

बैंकिंग पहुंच — बैंक सखी जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाएं डिजिटल बैंकिंग और औपचारिक वित्तीय प्रणालियों से जुड़ती हैं।

सुरक्षा, संरक्षा और संवर्धन मिला – महिलाओं के अधिकार

1. घरेलू हिंसा से सुरक्षा का अधिकार — घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत महिलाओं को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानूनी सुरक्षा मिलती है।

2. समान वेतन का अधिकार

3. कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार — कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (POSH Act) महिलाओं को ऑफिस या कार्यस्थल पर सुरक्षित माहौल और शिकायत दर्ज करने का अधिकार देता है।

4. दहेज के खिलाफ अधिकार — दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के तहत दहेज लेना और देना कानूनी अपराध है।

5. मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार — विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत देश की किसी भी महिला को न्याय पाने के लिए मुफ्त वकील और मुफ्त कानूनी सेवाएं दी जाती हैं।

6. रात में गिरफ्तारी न किए जाने का अधिकार — कानून के मुताबिक, किसी भी सामान्य स्थिति में सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले महिलाओं को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।

7. गोपनीयता का अधिकार — बलात्कार या यौन उत्पीड़न से पीड़ित महिलाओं की पहचान को कानूनी और पुलिस प्रक्रियाओं के दौरान गुप्त रखा जाता है ताकि उनकी गरिमा बनी रहे।

8. वर्चुअल या ऑनलाइन शिकायत का अधिकार — यदि कोई महिला थाने जाने में असमर्थ है, तो वह ईमेल या ऑनलाइन माध्यम से अपनी शिकायत पुलिस को भेज सकती है।

9. मातृत्व लाभ का अधिकार — मातृत्व हितलाभ अधिनियम के तहत कामकाजी महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान सवेतन अवकाश और अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं पाने का अधिकार है।

10. संपत्ति में समान अधिकार — हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और अन्य संपत्ति कानूनों के अनुसार महिलाओं को अपने पैतृक और परिवार की संपत्ति में पुरुषों के समान अधिकार मिलते हैं।

11. गरिमा और समानता का अधिकार — संविधान और कानून महिलाओं को गरिमा, समानता और स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार देते हैं। किसी भी प्रकार के भेदभाव के खिलाफ कानूनी सुरक्षा उपलब्ध है।

चूल्हा-चौका तक सीमित जिंदगी से आत्मनिर्भरता की उड़ान

कभी घर की चारदीवारी तक सीमित जिंदगी जीने वाली सूरजपुर जिले के मसीरा गांव की श्रीमती लक्ष्मनिया दीदी ने आज आत्मनिर्भरता की ऐसी मिसाल कायम की है, जो ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रेरणा बन रही है। परिवार की जिम्मेदारियों के बीच अपने लिए कोई अलग पहचान बनाने की कल्पना करने वाली लक्ष्मनिया दीदी आज न केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हैं, बल्कि गांव में डिजिटल सेवाओं की महत्वपूर्ण कड़ी बनकर ग्रामीणों को सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं। अपनी मेहनत और शासन की योजनाओं से मिले अवसरों के बूते वे लखपति दीदी बन चुकी हैं।

विष्णु भैया की पहल से तालाब बना महिलाओं की तरक्की का आधार

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार महिलाओं को आजीविका के विभिन्न साधनों से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। शासन की योजनाओं और विभागीय सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं अब पारंपरिक गतिविधियों के साथ-साथ मछली पालन जैसे लाभकारी व्यवसाय को अपनाकर अपनी आय बढ़ा रही हैं।जशपुर जिले के मनोरा और दुलदुला विकासखंड की महिला स्व-सहायता समूहों ने शासकीय तालाबों को अपनी आजीविका का आधार बनाकर आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्रेरक मिसाल पेश की है।

मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने बालिका गृह की बेटियों के साथ सुनी 'मन की बात'

महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने शासकीय बालिका गृह, शंकर नगर रायपुर में बेटियों के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम का 137वां संस्करण सुना। इस अवसर पर मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने बेटियों के साथ आत्मीय संवाद करते हुए उनके सपनों, उत्साह और आत्मविश्वास को करीब से जाना। मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि बेटियों के साथ बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों को सुनना उनके लिए बेहद आत्मीय और सुखद अनुभव रहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का 'मन की बात' कार्यक्रम देशवासियों को सकारात्मक सोच, नवाचार, आत्मनिर्भरता और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करता है।

नोनी सुरक्षा योजना दे रही बेटियों के भविष्य को नई उम्मीद

गौरेला विकासखंड के ग्राम पंचायत सारबहरा की श्रीमती आकांक्षा अपनी बेटी के उज्ज्वल भविष्य को लेकर हमेशा चिंतित रहती थीं। उनकी इच्छा थी कि बेटी को अच्छी शिक्षा मिले और आगे चलकर उसका जीवन सुरक्षित, आत्मनिर्भर और खुशहाल हो। इसी चिंता को कम करने और बेटी के भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाने की दिशा में आकांक्षा ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से अपनी बेटी का 'नोनी सुरक्षा योजना' के तहत पंजीयन कराया। योजना से मिलने वाली आर्थिक सुरक्षा के भरोसे ने उनके मन में बेटी के भविष्य को लेकर नई उम्मीद जगाई है।

खीरे की खेती से सुभद्रा मंडल ने लिखी आत्मनिर्भरता की नई कहानी

अम्बिकापुर विकासखंड के ग्राम पंचायत सकालो की रहने वाली श्रीमती सुभद्रा मंडल की। काली माँ स्व-सहायता समूह से जुड़ने के बाद सुभद्रा ने समूह के माध्यम से 1 लाख रुपए का ऋण लिया और इस राशि का उपयोग कर एक एकड़ भूमि में खीरे की खेती शुरू की। खेती के इस प्रयास के साथ उन्होंने अपनी आय बढ़ाने और परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

महतारी वंदन योजना से सीमा को मिला आर्थिक संबल

मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के ग्राम पाडारवानी निवासी श्रीमती सीमा उइके के लिए महतारी वंदन योजना की 31वीं किस्त के रूप में मिली एक हजार रुपए की राशि बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की राह में महत्वपूर्ण सहारा बन रही है। रक्षाबंधन से पहले खाते में राशि पहुंचने से सीमा उइके की खुशियां दोगुनी हो गईं। उन्होंने कहा कि, विष्णु भैया ने सितंबर माह की राशि अगस्त में ही देकर हम बहनों को रक्षाबंधन का उपहार दिया है। इससे हमारी खुशियां दोगुनी हो गई हैं।

मेटल पार्क के पास सड़क किनारे मिली लाश, जांच में जुटी पुलिस

शहर सत्ता/रायपुर। राजधानी रायपुर के खमतराई थाना क्षेत्र में सड़क किनारे अधेड की लाश मिलने से हडकंप मच गई। मृतक की

शिनाख्त फाफाडीह निवासी कैलाश निर्मलकर के रुप में हुई है। मृतक प्रायवेट कंपनी में जॉब करता था। शराब पीने का आदि था और शनिवार की शाम से लापता था। रविवार की सुबह स्थानीय लोगों ने सड़क किनारे शव पड़ा देखा, जिसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही खमतराई थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर परिजनों को सूचना दी है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार मृतक का शव सड़क किनारे नाली में पड़ा हुआ था। पुलिस फिलहाल यह पता लगाने में जुटी है कि व्यक्ति की मौत किन परिस्थितियों में हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों के फुटेज की जांच कर रही है। इसके अलावा घटनास्थल के आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ और अन्य साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है।

रात गश्त पर गया था आरक्षक, पीछे से चोरों ने कर दिया घर साफ

शहर सत्ता/रायपुर। राजधानी रायपुर में पुलिसकर्मी के घर चोरी का मामला सामने आया है। पंडरी थाना क्षेत्र के दुबे कॉलोनी स्थित ग्रैंडले विहार में चोरों ने महिला थाना में पदस्थ आरक्षक दीपक पटेल के घर को निशाना बनाया। वारदात के समय आरक्षक रात्रि गश्त पर गया था, जबकि उसकी पत्नी और बच्चे भी घर पर नहीं थे। पंडरी पुलिस के मुताबिक रक्षाबंधन के मौके पर दीपक पटेल की पत्नी और बच्चे गांव गए हुए थे। घर में किसी के नहीं होने का फायदा उठाकर चोर देर रात मकान में घुस गए। चोरों ने पहले मुख्य दरवाजे का ताला तोड़ा। इसके बाद अंदर रखी अलमारियों के लॉक तोड़कर नकदी और जेवरात चोरी कर लिए। रात्रि गश्त से लौटने के बाद आरक्षक दीपक पटेल घर पहुंचा तो मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ मिला। अंदर जाकर देखा तो सामान बिखरा पड़ा था और अलमारियों के ताले भी टूटे हुए थे। जांच करने पर नकदी और जेवर चोरी होने की जानकारी सामने आई। घटना की सूचना मिलते ही पंडरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। चोरी की गंभीरता को देखते हुए FSL टीम, डॉग स्क्वायड और क्राइम टीम को भी बुलाया गया। टीमों ने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं।

चाकू की नोक पर अफसर की पत्नी से रेप, आरोपी को उम्रकैद

शहर सत्ता/रायपुर। रायपुर में ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी की टीचर पत्नी से चाकू की नोक पर बंधक बनाकर रेप का मामला सामने आया था। इस केस में 5 साल की सुनवाई के बाद फैसला आया है। अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) विनय कुमार प्रधान की अदालत ने आरोपी बालकृष्ण जांगड़े को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने आरोपी पर 1 लाख 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं, आरोपी की पत्नी अंजना जांगड़े को पर्याप्त सबूत नहीं मिलने पर कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया। जानकारी के मुताबिक, मामला 15 मार्च 2021 का है। आरोपी बालकृष्ण जांगड़े और उसकी पत्नी अंजना जांगड़े मूल रूप से बेमेतरा के रहने वाले हैं और रायपुर के पिरदा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहते थे। वारदात के समय पीड़िता अपने दो बच्चों के साथ घर पर अकेली थी। पति सुबह करीब 10 बजे ऑफिस चले गए थे। पीड़िता के अनुसार, आरोपी शादी का कार्ड देने के बहाने घर पहुंचा। उसने खुद को पति का दोस्त बताया। इसके बाद पति का परिचित होने की बात कहकर घर के अंदर घुस गया। पीड़िता ने कोर्ट में दिए बयान में बताया कि आरोपी ने घर में घुसने के बाद उस पर चाकू से हमला किया। इसके बाद उसे बंधक बना लिया। घर में उस समय उसके 12 और 4 साल के दो बच्चे भी मौजूद थे। पीड़िता के अनुसार, आरोपी ने बच्चों के सामने ही रेप किया। वारदात के दौरान पीड़िता के शरीर पर कई चोटें आई। उसने 12:45 बजे अपने पति को फोन कर घर में 2 लोगों के घुसने और चाकू से हमला करने की जानकारी दी। सूचना मिलने पर पति घर पहुंचा तो पत्नी घायल अवस्था में मिली।

अब कोर्ट जाने की जरूरत नहीं, पीड़ित को थाने में देना होगा सिर्फ 100 रुपए का बॉन्ड

साइबर ठगी के शिकार पीड़ितों को 50 हजार तक की राशि पाना हुआ आसान

शहर सत्ता/रायपुर। साइबर ठगी के शिकार लोगों या जिनकी रकम ठगों के खातों में होल्ड कराई गई है, उन्हें पैसा वापस पाने के लिए अब थाने और कोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। केंद्र की नई गाइडलाइन के बाद छत्तीसगढ़ में भी होल्ड रकम वापस दिलाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए पीड़ितों को क्षतिपूर्ति बॉन्ड भरना पड़ रहा है। रायपुर में इसके लिए 100 रुपए का बॉन्ड लिया जा रहा है। हालांकि स्पष्ट निर्देश नहीं होने के कारण कुछ जगह 1000 रुपए तक का बॉन्ड लिया जा रहा है। इंडियन स्टाम्प एक्ट-1899 के तहत क्षतिपूर्ति बॉन्ड के लिए 1000 रुपए की स्टाम्प ड्यूटी है। यानी किसी को 500 रुपए भी वापस लेने हैं तो 1000 रुपए का बांड भरना पड़ सकता है।

साइबर ठगी के पीड़ितों के लिए गृह मंत्रालय और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने मनी रीस्टोरेशन मॉड्यूल (MRM) और ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म (GRM) पोर्टल लॉन्च किया है। नई व्यवस्था में 50 हजार रुपए तक की होल्ड रकम पुलिस के पास क्षतिपूर्ति बांड जमा करने के बाद एक सप्ताह के भीतर वापस मिल सकेगी। नरेश पटेल, एसीपी साइबर सेल के मुताबिक यह बांड एक तरह का शपथ पत्र है। इसमें पीड़ित को लिखकर देना होगा कि कोर्ट के निर्देश पर वह रकम वापस करने के लिए सहमत है। पिछले तीन साल में 68000 लोगों से 729 करोड़ की ठगी: पुलिस विभाग से मिले आंकड़ों पर नजर डालें तो राज्य में पिछले तीन साल में 68,000 लोगों से 729 करोड़ रुपए की ठगी हुई। इसमें से 72 करोड़ रुपए होल्ड कराए गए।

इसलिए जरूरी है बॉन्ड

साइबर ठगी के मामले में बॉन्ड भरना इसलिए जरूरी है, क्योंकि राशि लौटाने के बाद कोई दूसरा दावेदार अदालत पहुंचता है या अदालत किसी अन्य वैधानिक कारण से रकम वापस मांगती है तो संबंधित व्यक्ति उत्तरदायी रहेगा। आई4सी ने आदेश जारी किया है। राजस्थान में बॉन्ड राशि 200 रुपए, इंदौर में 500 और भोपाल में 1000 रुपए है। रायपुर में अभी 100 रुपए का बॉन्ड लिया जा रहा है।

50 हजार की ठगी में FIR जरूरी नहीं

साइबर ठगी में 50 हजार रुपए तक की फ्रीज रकम वापस लेने के लिए पीड़ित को एफआईआर या कोर्ट के आदेश की जरूरत नहीं होगी। पुलिस पीड़ित से क्षतिपूर्ति बॉन्ड भरवाएगी। फिर रकम खाते में जमा की जाएगी। साइबर ठगी में सिंगल खाते में 50 हजार रुपए से अधिक रकम होल्ड होने पर एफआईआर जरूरी होगी। एमआरएम पोर्टल पर रिक्वेस्ट के बाद पुलिस टीम क्षतिपूर्ति बॉन्ड और नोटिस अपलोड करेगी। फिर पैसे मिलेंगे।

ऐसे मिलेगी होल्ड राशि

- मनी रेस्टोरेशन सिटीजन पोर्टल https://mrm-ncrp.mha.gov.in पर जाएं।
- एक्नॉलेजमेंट नंबर या ओटीपी से लॉगइन करें।
- स्पष्ट रूप से दिखेगा कि किस बैंक खाते में आपकी कितनी राशि होल्ड की गई है।
- आईएफएससी कोड, बैंक डिटेल्स, धोखाधड़ी की राशि का विवरण, पैन कार्ड, एफआईआर की कॉपी, कोर्ट का रिफंड ऑर्डर अपलोड करें।
- 'Raise Request For Refund' पर क्लिक करें। इसके बाद यूनिक आईडी नंबर जेनरेट होगा।
- आपकी रिक्वेस्ट जांच अधिकारी तक पहुंचेगी।
- सत्यापन और पीड़ित से बॉन्ड लेने के बाद खाते में राशि रिफंड कर दी जाएगी।

पुलिस कमिश्नरेट की बड़ी कार्रवाई 30 स्पा सेंटरों में एक साथ जांच

शहर सत्ता/रायपुर। शहर में संचालित विभिन्न स्पा सेंटरों की सघन जांच करने के उद्देश्य से आज पुलिस कमिश्नरेट रायपुर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में संचालित 30 अलग-अलग स्पा सेंटरों में एक साथ जांच अभियान चलाया गया। कार्रवाई के लिए पुलिस की 15 टीमों का गठन किया गया, जिसमें राजपत्रित अधिकारियों सहित 100 से अधिक पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल रहे। पुलिस उपायुक्त वेस्ट जोन रॉबिन्सन गुरिया, पुलिस उपायुक्त सेंट्रल जोन तारकेश्वर पटेल एवं पुलिस उपायुक्त नॉर्थ जोन दीपमाला कश्यप के निर्देशन में तीनों जोन में कार्यवाही की गई। सहायक पुलिस आयुक्त स्नेहिल साहू, नंदिनी ठाकुर एवं पूर्णिमा लामा के नेतृत्व में गठित पुलिस टीमों द्वारा उक्त जांच कार्रवाई की गई।

पुलिस की 15 टीमों ने 100 से अधिक अधिकारी-कर्मचारियों के साथ की जांच कार्रवाई

जांच के दौरान पुलिस टीमों द्वारा स्पा सेंटरों के ग्राहकों के रजिस्टर, CCTV कैमरों की उपलब्धता एवं रिकॉर्डिंग की क्षमता, संचालक, मैनेजर एवं कर्मचारियों के पुलिस वेरिफिकेशन, कर्मचारियों की आयु संबंधी दस्तावेज, एवं स्टाफ रजिस्टर सहित आवश्यक अभिलेखों की जांच की गई। इसके साथ ही स्पा सेंटरों में किसी प्रकार की प्रतिबंधित अथवा संदिग्ध गतिविधि, परिसर की व्यवस्था, लीज/किराया एवं स्वामित्व संबंधी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक अनुमतियों की भी जांच की गई।

जांच के दौरान 02 स्पा सेंटरों में आपत्तिजनक वस्तुएं पाए जाने पर संबंधित मैनेजर एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। इनमें थाना डीडी नगर क्षेत्र अंतर्गत एलिना स्पा सेंटर तथा थाना पंडरी क्षेत्र अंतर्गत अंबुजा मॉल में संचालित ला थाई स्पा सेंटर शामिल हैं। उक्त दोनों स्पा सेंटरों के मैनेजर एवं कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा स्पा सेंटरों की जांच एवं लगातार निगरानी रखी जा रही है।

रायपुर पुलिस मुस्तैद कट्टा, चाकू और हथियार बंद पर कार्रवाई जारी

शहर सत्ता/रायपुर। राजधानी पुलिस अवैध हथियार लेकर घूम रहे असामाजिक तत्वों के खिलाफ मुस्तैदी से कार्रवाई में जुट गई है। कट्टा, चाकू और हथियार बंद पर कार्रवाई जारी है। अवैध देशी कट्टा लेकर लोगों को भयभीत करने के आरोप में मोहम्मद अमीरुद्दीन उर्फ जीशान गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से एक लोहे का देशी कट्टा बरामद हुआ है। आरोपी के विरुद्ध थाना पुरानी बस्ती में अपराध क्रमांक 446/2026, धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध। इसी तरह 29 अगस्त को PWD ओव्हर ब्रिज एवं बूढी माता चौक राजेन्द्र नगर के पास दो अलग अलग व्यक्ति धारदार चाकू लेकर आम लोगो को आतंकित कर रहे थे। सूचना पर तत्काल थाना सिविल लाईन पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर प्रितम बाघ एवं लोमेश मंडावी को पकड़कर उनके कब्जे से एक एक नग धारदार चाकू जप्त कर गिरफ्तार किया। पुलिस उपायुक्त पश्चिम जोन रॉबिन्सन गुड़िया के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त पश्चिम जोन राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन तथा सहायक पुलिस आयुक्त पुरानी बस्ती देवांश सिंह राठौर के नेतृत्व में अवैध हथियार रखने एवं उनका प्रदर्शन कर भय का वातावरण निर्मित करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। 29 अगस्त को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति देशी कट्टा लेकर क्षेत्र में आने-जाने वाले लोगों को दिखाकर भयभीत कर रहा है। सूचना पर थाना पुरानी बस्ती पुलिस एवं पेट्रोलिंग टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई।

कटोरा तालाब में जुआ खेलते पकड़ाए 9 आरोपी

114500 लाख रूपये सहित 52 पत्ती ताश जप्त किया गया

शहर सत्ता/रायपुर। डीसीपी सेंट्रल जोन अंतर्गत सिविल लाइन थाना पुलिस ने कटोरा तालाब में 09 आरोपियों को जुआ खेलते पकडा। आरोपियों के कब्जे से फड से कुल नगदी रकम 114500/- रूपये सहित 52 पत्ती तास के जप्त किया गया। थाना सिविल लाईन पुलिस टीम द्वारा की गई कार्यवाही। आरोपियों के विरुद्ध थाना सिविल लाईन में अपराध क्रमांक 461/24 धारा 3(2), छ.ग. जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत की गई है कार्यवाही।

28 अगस्त को शाम को अभियान के तहत सउनि संतोष यादव, आर० कं. 1100 कमलेश सिंह, आर० क्र. 1920 सुनील चंदेल के रवाना हुए थे दौराना अभियान कार्यवाही के मुखबीर से सूचना पर ईलेवन स्टार ग्राउंड कटोरा तालाब में खंभे की रोशनी में कुछ जुआ खेल रहे हैं। खबर मिलते ही बल पहुंचा और गवाह मोहन धारवानी पिता दिलीप धारयानी काली नगर पण्डरी तथा जगदीश आरसवानी पिता स्व० सुरेश कुमार आसरवानी शिव मंदिर के पास तेलीबांध को मुखबीर सूचना से अवगत कराकर रेड कार्यवाही में सहयोग करने नोटिस दिया जो लिखित सहमती देने पर मुखबीर के बताये स्थान पर घेरा बंदी कर रेड कार्यवाही में मदद किये। मौके से रनवीर सिंह पिता मनमोहन सिंह उम्र 32 साल सा० बल्भ कालोनी रिंग रोड मकान नंबर सी 37 थाना टिकरापारा रायपुर 2 सागर बालानी पिता तुलसी दास बालानी उम्र 33 साल सा० विशाल नगर बी 5 तेलीबांधा रायपुर, यरुल श्रीवास्तव पिता प्रकाश श्रीवास्तव उम्र 30 साल सिविल लाईन सेन्ट्रल बैंक के सामने सिविल लाईन रायपुर,वैभव मल्होत्रा पिता योगेश मल्होत्रा उम्र 26 साल बजाज कालोनी सी 30 न्यु राजेन्द्र नगर रायपुर, किन्तव पारेख पिता मनोज पारेख उम्र 33 साल श्रीनगर दही हाण्डी मैदान थाना खमतराई रायपुर 6. अंकुर श्रीवास्तव पिता अधीर श्रीवास्तव उम्र 28 साल सा० छत्तीसगढ़ क्लब के पास सिविल लाईन रायपुर वरूण यदु पिता नीरज यदु उम्र 32 साल सा० महिला पालिटेकनिक के सामने बैरन बाजार रायपुर सागर शर्मा पिता प्रफुल शर्मा उम्र 28 साल ईस्ट 12 कचना खम्हारडीह रायपुर नमन अग्रवाल पिता मनोज अग्रवाल उम्र 28 साल शंकर नगर टर्निंग पाईट चौक खम्हारडीह रायपुर को गिरफ्तार किया गया।

खारून-नदी में डूबे युवक का 30 घंटे बाद SDRF ने किया शव बरामद

रक्षाबंधन पर बहन की अस्थियां विसर्जित करने पहुंचा था

शहर सत्ता/रायपुर। राजधानी रायपुर में रक्षाबंधन के दिन खारुन नदी में डूबे युवक का शव करीब 30 घंटे बाद बरामद कर लिया गया है। युवक अपनी बहन की अस्थियां विसर्जित करने के लिए महादेव घाट पहुंचा था। इस दौरान वह नदी में डूब गया था। घटना के बाद से SDRF की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही थी। मृतक की पहचान युधिष्ठिर सारंग के रूप में हुई है। रक्षाबंधन के दिन युवक परिवार के साथ बहन की अस्थियां लेकर खारुन नदी पहुंचा था। अस्थि विसर्जन के दौरान वह भंवर में फंसकर एनिकट के पास डूब गया था। घटना डीडी नगर थाना क्षेत्र के महादेव घाट की है। युवक के नदी में डूबने की सूचना मिलते ही SDRF की टीम मौके पर पहुंची और तलाश शुरू की। टीम ने नदी के अलग-अलग हिस्सों में सर्च ऑपरेशन चलाया। पानी की गहराई और तेज बहाव के कारण रेस्क्यू टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी। करीब 30 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद SDRF की टीम ने युवक का शव नदी से बरामद कर लिया। शव मिलने के बाद मौके पर मौजूद परिजनों में मातम छा गया।

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

बहन की अस्थियों का विसर्जन करने पहुंचे परिवार के लिए यह हादसा बेहद दर्दनाक रहा। जिस दिन परिवार बहन को अंतिम विदाई देने नदी पहुंचा था, उसी दिन भाई की भी मौत हो गई। घटना के बाद से परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हादसे के बाद प्रशासन ने लोगों से नदी में उतरते समय सावधानी बरतने और गहरे पानी में जाने से बचने की अपील की है।

18 निगम मंडल के पदाधिकारियों को मिला मंत्री का दर्जा

ममता साहू, रामलाल, रूप सिंह को कैबिनेट रैंक, गौरीशंकर श्रीवास समेत 15 को राज्यमंत्री का दर्जा

शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने अलग-अलग निगम, बोर्ड और आयोग के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा दिया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक, कुल 18 पदाधिकारियों को मंत्री का दर्जा दिया गया है। इनमें 3 को कैबिनेट मंत्री और 15 को राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। वहीं, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी को पहले 29 अक्टूबर 2025 के आदेश में राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था। अब इस आदेश में बदलाव करते हुए उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है।

ममता साहू

गौरीशंकर श्रीवास

सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रामलाल चौहान, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी और छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. ममता साहू को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है।

15 को राज्य मंत्री का दर्जा

वहीं, सरकार ने 15 अन्य पदाधिकारियों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया है। इनमें गौरिशंकर श्रीवास, आनंद निषाद, राजेश कुमार राजपूत, राजेंद्र नायक, सुधीर गौतम, एजाज मिर्जा बेग, भोजराज देवांगन, प्रभात मिश्रा, सुषमा जेठानी, शशिकांत द्विवेदी, डॉ. जेपी शर्मा, किशोर महानंद, आनंद कुमार तिवारी (राजीव लोचन दास महाराज), वेदराम मनहरे और मंगल दास ठाकुर शामिल हैं। इनमें निगम-मंडलों और आयोगों के अध्यक्षों के साथ कुछ उपाध्यक्ष भी शामिल हैं।

27 अगस्त से आदेश लागू

सरकार ने कहा है कि इस सूची से किसी की वरिष्ठता या प्रोटोकॉल तय नहीं होता। यह नया आदेश 27 अगस्त 2026 से लागू है।

नक्सलवाद की मुक्ति के बाद पहली बार बस्तर आएंगे राहुल

शहर सत्ता/रायपुर। बस्तर में नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई के बाद बदलते राजनीतिक और सामाजिक माहौल के बीच कांग्रेस अब राहुल गांधी को बस्तर लाने की तैयारी में जुट गई है। पार्टी की योजना जल-जंगल-जमीन से जुड़े मुद्दों को केंद्र में रखकर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने की है। इसके साथ ही आदिवासी समाज की समस्याओं, वनाधिकार, विस्थापन, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों की जमीनी जानकारी जुटाने के लिए एक विशेष समिति को जिम्मेदारी सौंपी गई है। कांग्रेस के रणनीतिकारों का मानना है कि बस्तर में सुरक्षा की स्थिति में आए बदलाव के बाद क्षेत्र की राजनीति भी नए दौर में प्रवेश कर रही है। ऐसे समय में पार्टी आदिवासी क्षेत्रों में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने के लिए विकास के साथ-साथ जल-जंगल-जमीन के पारंपरिक सवालों को प्रमुखता देना चाहती है। राहुल गांधी का संभावित दौरा इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इसके जरिए कांग्रेस यूसीसी और खदानों के आवंटन जैसे मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाएगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, प्रस्तावित समिति बस्तर संभाग के विभिन्न इलाकों में जाकर आदिवासी समाज की प्रमुख समस्याओं की जानकारी जुटाएगी। इसमें वनाधिकार पट्टे, भूमि से जुड़े मामले, विस्थापन और पुनर्वास, स्थानीय रोजगार, लघु वनोपज, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा बुनियादी सुविधाओं से जुड़े विषय शामिल किए जा सकते हैं।

फार्मेसी कॉलेजों में 1 सितंबर से शुरू होगी काउंसलिंग

शहर सत्ता/रायपुर। प्रदेश के फार्मेसी कॉलेजों में प्रवेश का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। तकनीकी शिक्षा संचालनालय ने काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। पहले चरण के लिए ऑनलाइन पंजीयन एक से पांच सितंबर तक होंगे। छह सितंबर को मेरिट सूची जारी की जाएगी और सात सितंबर को दावा-आपत्ति का मौका मिलेगा। आपत्तियों के निराकरण के बाद आठ सितंबर को सीटों का पहला आवंटन होगा। आवंटित सीट पर 9 से 11 सितंबर तक प्रवेश लेना होगा। दूसरे चरण के लिए 13 से 16 सितम्बर तक पंजीयन होंगे। मेरिट सूची 17 सितम्बर को जारी होगी और 18 सितंबर शाम पांच बजे तक दावा-आपत्ति की जा सकेगी। 19 सितंबर को सीट आवंटन के बाद 20 से 22 सितंबर तक संबंधित कॉलेज में प्रवेश लेना होगा। सीटें खाली रहने पर तीसरे चरण की काउंसलिंग संस्था स्तर पर होगी। इसके लिए 24 से 26 सितंबर तक पंजीयन और 27 सितंबर को मेरिट सूची जारी की जाएगी। मेरिट के आधार पर संस्था स्तर पर सीट आवंटन के लिए अभ्यर्थी को 28 सितंबर सुबह 10 बजे संबंधित कॉलेज में उपस्थित होना होगा। प्रवेश प्रक्रिया 28 सितम्बर दोपहर एक बजे से 29 सितम्बर दोपहर एक बजे तक चलेगी।

अंबिकापुर में कांग्रेस नेता गुरुप्रीत सिंह सिद्धू पर हुआ जानलेवा हमला

शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में कांग्रेस नेता गुरुप्रीत सिंह सिद्धू पर शनिवार देर रात घर में घुसकर हमला किया गया। आरोप है कि 15 से 20 लोगों ने उनके साथ मारपीट की, जिसमें उनकी आंख में गंभीर चोट आई। घटना के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले में पुरानी राजनीतिक रंजिश का एंगल भी सामने आ रहा है। कांग्रेस नेता ने भाजपा नेता पर हमला कराने का आरोप लगाया है, जबकि भाजपा नेता ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है। मामला मणिपुर थाना क्षेत्र के दर्रीपारा इलाके का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार, शनिवार रात हथियारों से लैस करीब 15 से 20 लोग कांग्रेस नेता गुरुप्रीत सिंह सिद्धू के घर पहुंचे। आरोप है कि घर में घुसने के बाद उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट की गई। हमले में सिद्धू की आंख में गंभीर चोट आई है। घटना के बाद परिजन और आसपास के लोगों की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज कराया जा रहा है। घटना के पीछे पुरानी राजनीतिक रंजिश की बात भी सामने आ रही है। गुरुप्रीत सिंह सिद्धू पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के करीबी माने जाते हैं। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया है कि राजनीतिक विवाद के चलते उनके साथ यह हमला कराया गया।

भाजपा सरकार कर रही युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़

शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के सपने भर्ती परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ियों के कारण टूट रहे हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार की लापरवाही और संरक्षण के कारण भर्ती एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता लगातार सवालों के घेरे में आ रही है। प्रदेश कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में तीन पेपर लीक होने का मामला सामने आया है। यह तो केवल वे मामले हैं जिनका खुलासा हुआ है। सवाल यह है कि अगर एक ही संस्थान में तीन परीक्षाओं के पेपर लीक हो सकते हैं, तो प्रदेश में आयोजित अन्य भर्ती परीक्षाओं की निष्पक्षता की गारंटी सरकार कैसे दे सकती है?प्रदेश कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद आरक्षक भर्ती, वनरक्षक भर्ती, आरआई प्रमोशन, पीडब्ल्यूडी सब इंजीनियर भर्ती और पीएससी की एएसआई भर्ती सहित विभिन्न परीक्षाओं और चयन प्रक्रियाओं में गड़बड़ियों एवं विवादों के आरोप सामने आए हैं। इससे प्रदेश के युवाओं के मन में सरकारी भर्ती प्रक्रिया को लेकर अविश्वास पैदा हुआ है। कांग्रेस सरकार से मांग करती है कि सभी विवादित भर्ती परीक्षाओं और चयन प्रक्रियाओं की निष्पक्ष एवं स्वतंत्र जांच कराई जाए।

विकास और जनहित के मुद्दे लंबित, सूरजपुर में 2 माह से नगर-पालिका परिषद की बैठक नहीं

शहर सत्ता/.न्यूज़ डेस्क। सूरजपुर में नगर पालिका परिषद की बैठक दो माह से आयोजित नहीं होने पर भाजपा पार्षद दल ने नाराजगी जताई है। पार्षदों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जल्द परिषद की बैठक बुलाने की मांग की है। पार्षदों ने बताया कि बैठक को लेकर लगातार ध्यानाकर्षण कराया जा रहा है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। भाजपा पार्षद दल ने ज्ञापन में कहा कि परिषद की बैठक नहीं होने से नगर के कई महत्वपूर्ण विकास और जनहित से जुड़े विषयों पर चर्चा और निर्णय लंबित हैं। पार्षदों के अनुसार, परिषद की बैठक लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां शहर के विकास से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा कर आवश्यक निर्णय लिए जाते हैं। ज्ञापन में नजूल भूमि के नवीनीकरण, शहर विकास से जुड़े कार्य, आदर्श नगर पालिका के कार्य, तालाब सौंदर्यीकरण, चौपाटी व्यवस्था और दुकानों की नीलामी सहित कई विषयों को बैठक के एजेंडे में शामिल करने की मांग की गई है। पार्षदों ने इन विषयों पर चर्चा कर जल्द निर्णय लेने की मांग की है।

बिजली के निजीकरण की तैयारी जनता के साथ विश्वासघात है: कांग्रेस

शहरसत्ता/रायपुर। बिजली के निजीकरण की तैयारी जनता के साथ विश्वासघात है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने बिजली के दाम बढ़ाकर, 400 यूनिट तक मिलने वाली राहत को खत्म कर और स्मार्ट मीटर के नाम पर आम जनता पर अतिरिक्त बोझ डालने के बाद अब बिजली व्यवस्था को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी शुरू कर दी है। जनता के खून-पसीने की कमाई से खड़ी की गई बिजली कंपनी को बेचने और निजी कंपनियों को बिजली सप्लाई का ठेका देने की सरकार की तैयारी छत्तीसगढ़ की जनता के हितों के साथ सीधा विश्वासघात है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि पहले मंत्रिमंडल में विद्युत कंपनी के शेयर बेचने का फैसला लिया गया और अब निजी कंपनी को बिजली सप्लाई का ठेका देने की तैयारी की जा रही है। जब सरकारी बिजली कंपनी प्रदेश की जनता को बिजली उपलब्ध करा रही है तो उसे कमजोर कर निजी

कंपनियों को फायदा पहुंचाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? कांग्रेस स्पष्ट रूप से कहना चाहती है कि हर परिवार, किसान, मजदूर और छोटे व्यवसाय की बुनियादी जरूरत है। बिजली व्यवस्था का निजीकरण हुआ तो इसका सीधा असर आम उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा और भविष्य में बिजली के दाम बढ़ने का रास्ता और आसान हो जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकार पहले ही बिजली के दाम बढ़ा चुकी है। 400 यूनिट तक मिलने वाली राहत को खत्म किया जा चुका है। स्मार्ट मीटर के नाम पर उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ी है। अब सरकारी बिजली व्यवस्था को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी इस बात का संकेत है कि सरकार की प्राथमिकता जनता को सस्ती बिजली देना नहीं, बल्कि निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाना है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस इस फैसले का पुरजोर विरोध करती है। हम सरकार से मांग करते हैं कि विद्युत कंपनी के शेयर बेचने और निजी कंपनियों को बिजली सप्लाई का ठेका देने की प्रक्रिया तत्काल रोकी जाए। छत्तीसगढ़ की बिजली व्यवस्था जनता की संपत्ति है, किसी निजी कंपनी की कमाई का जरिया नहीं। कांग्रेस जनता की लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ेगी।

भाजपा सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में रोजगार घटा - कांग्रेस

कांग्रेस सरकार में बेरोजगारी दर 0.60 प्रतिशत था जो ढाई साल में 4.5 प्रतिशत है

शहर सत्ता/रायपुर। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा सरकार ढाई साल में एक भी युवा को रोजगार नहीं दे पायी है, बल्कि युवाओं से रोजगार छीनने का ही काम किया है। कांग्रेस सरकार में बेरोजगारी दर मात्र 0.60 प्रतिशत था। भाजपा सरकार बनने के बाद बेरोजगारों की संख्या में भारी वृद्धि हुआ है।

आज बेरोजगारी दर 4.5 प्रतिशत है। ढाई साल में बीएड शिक्षक, अतिथि शिक्षक, विद्या मितान, क्रेडा के संविदा कर्मचारी, अनियमित कर्मचारी, विद्युत विभाग के कर्मचारी, वन विभाग के संविदा कर्मचारियों, गोठान महिला स्व सहायता समूह, रीपा के तहत रोजगार प्राप्त कर रहे लोगों को काम से बेदखल किया गया, ई-श्रेणी के लाइसेंस में काम कर रहे युवाओं से भी काम छिन गया है, पूरे प्रदेश में विकास कार्य ठप है कोई नई भर्ती पूरी नहीं हुई है पूर्व से चल रही भर्ती में भी नियुक्तियां नहीं दी जा रही है हर विभाग में काम करने वाले युवाओं से उनका हक अधिकार को छीना गया है। ऐसे में साय सरकार का रोजगार देने का दावा सरासर जुमला और मनगढ़ंत आंकड़े हैं।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि ढाई साल में कितने युवाओं को सरकारी नौकरी में भर्ती का अवसर दिया गया है कितने मजदूरों को काम दिया गया है रोजगार देने के लिए क्या नई योजना लायी गई है? भाजपा की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में यूपी की तरह युवा रोजगार के लिए सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं सिर का मुंडन करवा रहे हैं बीएड, डीएड शिक्षक आंदोलन कर रहे।

भूपेश ने सोनिया को बताया निडर कहा; उनकी किताब से BJP को खतरा

शहर सत्ता/रायपुर। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की किताब 'Belonging' को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भाजपा पर हमलावर हैं। किताब के भारत में प्रकाशन को लेकर सामने आई खबरों के बाद बघेल ने सोनिया गांधी का समर्थन करते हुए कहा कि कायर लोग किताबों और विचारों से डरते हैं। बघेल ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा- "कायर लोग किताबों से डरते हैं! किताबों के छपने और पढ़े जाने से डरते हैं।" उन्होंने कहा कि इसी डर की वजह से किताब छापने वालों को डराया-धमकाया जाता है। बघेल के मुताबिक, सोनिया गांधी की किताब दुनियाभर में प्रकाशित हो रही है, लेकिन भारत में एक प्रकाशक ने इसे छापने से इनकार कर दिया है। उन्होंने इसे कायराना हरकत बताते हुए कहा कि किताब आएगी और पढ़ी भी जाएगी। मीडिया से बातचीत में भी बघेल ने इसी मुद्दे पर भाजपा को घेरा। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी निडर महिला हैं।

भाजपा का सेवा संकल्प, स्कूलों में मोदी सरकार के सेवा कार्यों पर स्पर्धा

शहर सत्ता/रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के कार्यकाल को जन-जन तक पहुंचाने के लिए भाजपा 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक 'सेवा संकल्प' अभियान चलाएगी। इसमें बूथ से लेकर गांव, शहर और परिवार तक कार्यक्रम होंगे। इस कड़ी में देश के सरकारी और निजी स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए 'विकसित भारत' की संकल्पना और मोदी सरकार के सेवा कार्यों पर चित्रकला और भाषण प्रतियोगिताएं होंगी। शनिवार को कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में सेवा संकल्प अभियान को लेकर प्रदेशस्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। भाजपा राष्ट्रीय मंत्री व राज्यसभा सांसद डॉ. कविता पाटीदार ने कहा कि यह अभियान मात्र एक आयोजन नहीं, बल्कि सेवा, समर्पण और राष्ट्र निर्माण का व्यापक जनआंदोलन बनेगा। इसमें गांव, शहर, बूथ और परिवार की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय ने कार्यशाला में संगठनात्मक विषय पर कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया और आगामी कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला।

भाजपा प्रदेश महामंत्री और कार्यक्रम के प्रदेश संयोजक यशवंत जैन ने आगामी कार्यक्रमों की विस्तृत रूपरेखा साझा करते हुए बताया कि पार्टी हर साल 'सेवा पखवाड़ा' आयोजित करती रही है, लेकिन इस बार का आयोजन व्यापक होगा। कार्यशाला में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल, केन्द्रीय मंत्री तोखन साहू, प्रदेश सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि, जिलाध्यक्ष एवं भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहें।

सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाना है: सीएम

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि राज्य निर्माण के समय नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रभारी थे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के प्रत्येक जिले का दौरा कर संगठन को मजबूती दी थी। उनका छत्तीसगढ़ से बहुत पुराना और अटूट नाता है। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वे निरंतर राज्य के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं स्वीकृत कर रहे हैं। सीएम ने पार्टी कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों से कहा कि वे 'सेवा ही संकल्प' अभियान के माध्यम से केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाएं।

सेवा संकल्प अभियान खास क्यों

7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी ने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। 2026 में उनके सार्वजनिक पद पर 25 वर्ष (13 साल सीएम और 12 साल पीएम) पूरे हो रहे हैं। पार्टी इस 25 साल के कार्यकाल को सुशासन और स्थिरता के एक ब्रांड के रूप में स्थापित करना चाहती है। लिहाजा पार्टी की नजर मौजूदा के साथ-साथ भविष्य के वोटरों पर भी है। यही वजह है कि छात्रों के बीच भाषण व ड्राइंग प्रतियोगिता कराकर पार्टी उनके मन में विकसित भारत 2047 की वैचारिक छाप छोड़ना चाहती है।

कांग्रेस नेता धनंजय बोले; महादेव सट्टा ऐप अवैध है तो बंद क्यों नहीं?

जीएसटी नोटिस देकर भाजपा सरकार ने सट्टेबाजी को वैध कर दिया क्या?

शहर सत्ता/रायपुर। प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि महादेव सट्टा ऐप को लेकर भाजपा सरकार देश और प्रदेश की जनता को स्पष्ट करे कि महादेव सट्टा ऐप वैध है या अवैध? अगर यह अवैध है तो फिर इस पर पूरी तरह प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जा रहा है? और अगर अवैध कारोबार करने वाले ऐप संचालकों को जीएसटी वसूली की नोटिस दी जा रही है, तो सरकार बताए कि क्या टैक्स की नोटिस देकर सट्टेबाजी के अवैध कारोबार को वैधता का प्रमाणपत्र दिया जा रहा है?

प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि एक तरफ सरकार महादेव सट्टा ऐप को अवैध बताती है, दूसरी तरफ उसके कारोबार पर जीएसटी की गणना और वसूली का नोटिस जारी करती है। यह दोहरा रवैया देश की जनता की समझ से परे है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वह सट्टा बंद करना चाहती है या सट्टे से टैक्स वसूल कर उसे चलने देना चाहती है? प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि महादेव सट्टा ऐप के नेटवर्क के माध्यम से ऑनलाइन बैटिंग और मनी गेमिंग का कारोबार चलने की जानकारी जांच एजेंसियों को है। गोल्ड 365, लेजर 247, 11 एक्सप्ले, बेटबुक 247, सिल्वर एक्सचेंज, क्रिकेट बेट 9 और स्काई एक्सचेंज जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए क्रिकेट, फुटबॉल और टेनिस सहित विभिन्न खेलों पर कथित रूप से करोड़ों रुपये का दांव लगाया जाता है। जब जांच एजेंसियों और सरकार को इस पूरे नेटवर्क की जानकारी है, तो फिर इसे जड़ से खत्म करने के लिए निर्णायक कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है?

प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि यदि महादेव सट्टा ऐप अवैध है और इसके माध्यम से 1 लाख 43 हजार करोड़ रुपये के अवैध कारोबार का दावा किया गया है, तो सरकार बताए कि इस कथित अवैध कारोबार से जुड़ी रकम की जब्ती और संपत्तियों पर कार्रवाई कितनी हुई? अवैध कारोबार को रोकने के बजाय जीएसटी नोटिस भेजना किस नीति का हिस्सा है?

प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने भाजपा सरकार से पूछा कि क्या अब देश-प्रदेश में नया नियम बन गया है कि सट्टा चलाओ, टैक्स भरो और कारोबार जारी रखो? क्या इसी तर्ज पर अवैध सट्टा-पट्टी, नशीले पदार्थों की तस्करी, रेत तस्करी और गांजा तस्करी करने वालों से भी जीएसटी वसूल कर उन्हें कारोबार की अनुमति दे दी जाएगी?

संपादकीय

• सुकांत राजपूत

नेपाल में बाढ़ की तबाही ने फिर चेताया

तिब्बत से लगे नेपाल के रसुवा और आसपास के क्षेत्रों में बुधवार को आई बाढ़ से बड़े पैमाने पर हुए जान-माल के नुकसान ने सभी को झकझोर दिया है। इस त्रासदी में कई लोगों की जान चली गई, जबकि पांच सौ से ज्यादा लापता हैं, जिनमें सौ से अधिक भारतीय भी शामिल हैं। बाढ़ से कई पुल बह गए और कम से कम एक दर्जन जलविद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। प्रारंभिक अध्ययन रिपोर्टों और उपग्रह से ली गई तस्वीरों के विश्लेषण से पता चला है कि नेपाल-तिब्बत सीमा के पास पहाड़ी से चट्टानों के खिसकने के बाद बाढ़ आई। यानी यह हिमालय की संवेदनशीलता और उसकी पारिस्थितिकीय प्रकृति को समझने तथा विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने को लेकर एक गंभीर चेतावनी है। बाढ़ की खौफनाक तस्वीरों से यह समझना मुश्किल नहीं है कि जब प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है, तो मानव सभ्यता उसके आगे बेबस हो जाती है। प्रकृति और मनुष्य का संबंध अत्यंत गहरा एवं परस्पर निर्भरता पर आधारित है और जब इसमें कृत्रिम असंतुलन होता है, तो यह विनाशकारी घटनाओं का कारण बनता है।

खबरों के मुताबिक, सबसे पहले भोटे कोशी नदी में अचानक बाढ़ आई, जिससे तिब्बत की सीमा से लगे नेपाल के रसुवा और धादिंग जिले प्रभावित हुए। पानी और मलबे का बहाव इतना तेज था कि आसपास के धादिंग, नुवाकोट और चितवन जिले भी इसकी चपेट में आ गए। बाढ़ से लापता भारतीयों में से ज्यादातर तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे थे। नेपाल के बाढ़ पूर्वानुमान प्रभाग के मुताबिक, पहाड़ी से चट्टानों एवं मिट्टी के खिसकने से नदी अवरुद्ध हो गई और वहां बनी झील के टूटने से भीषण बाढ़ आई। यह त्रासदी इस बात का संकेत है कि हिमालयी क्षेत्र पारिस्थितिकीय रूप से कितना संवेदनशील है। प्रकृति हमें जल, वायु, भूमि, वन और जीवन के लिए आवश्यक अनेक संसाधन प्रदान करती है। मगर विकास और आधुनिक जीवन की दौड़ में मनुष्य ने प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने के बजाय उसका अंधाधुंध दोहन शुरू कर दिया है। जंगलों की कटाई, पहाड़ों का अतिक्रमण, नदियों के मार्गों में हस्तक्षेप और अनियोजित निर्माण जैसे कार्यों का परिणाम बाढ़ जैसी विनाशकारी त्रासदियों के रूप में सामने आ रहा है।

सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिन नदियों को नेपाल की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा-संभावना की जीवनरेखा माना जाता है, उन्हीं के किनारे बेतरतीब बस्तियां, सड़कें और अन्य ढांचागत संरचनाएं तैयार कर दी गई हैं। विकास आवश्यक है, लेकिन इस क्रम में पहाड़ों की प्रकृति की अनदेखी अंततः जोखिम का विस्तार बन जाती है। जलवायु परिवर्तन ने इस समस्या को और गंभीर बना दिया है। मौसम का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। कहीं लंबे समय तक सूखा पड़ता है, तो कहीं बहुत कम समय में अत्यधिक वर्षा या बादल फटने की घटनाएं बढ़ रही हैं। साफ है कि पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ बाढ़ जैसी त्रासदी को जन्म देती है। बहरहाल, विदेश मंत्रालय का कहना है कि नेपाल में बाढ़ से प्रभावित भारतीय नागरिकों के बचाव और उन्हें राहत पहुंचाने के लिए वहां की सरकार के साथ लगातार संपर्क एवं समन्वय किया जा रहा है। मगर, इस बाढ़ से नेपाल के साथ लगते बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी खतरा मंडराने लगा है। केंद्र और राज्य सरकारों को चाहिए कि वहां एहतियाती तौर पर सुरक्षा के माकूल प्रबंध किए जाएं, ताकि किसी तरह के नुकसान से बचा जा सके।

दृष्टिकोण का अंतर

एक बार एक प्रसिद्ध जूता कंपनी ने अपने व्यापार का विस्तार करने के लिए दो सेल्समैन को एक दूरदराज के द्वीप पर भेजा। उनका काम वहाँ जाकर बाजार की संभावनाओं का पता लगाना था। पहले सेल्समैन ने द्वीप पर पहुँचते ही देखा कि वहाँ रहने वाला कोई भी व्यक्ति जूते-चप्पल नहीं पहनता था। वह तुरंत निराश हो गया। उसने मुख्यालय को संदेश भेजा, "यहाँ व्यापार की कोई गुंजाइश नहीं है। कोई भी जूते नहीं पहनता, इसलिए मैं कल वापस लौट रहा हूँ।" उसी समय दूसरा सेल्समैन भी द्वीप के अलग-अलग कोनों में घूमा। जब उसने देखा कि किसी के पैरों में जूते नहीं हैं, तो उसकी आँखें खुशी और उत्साह से चमक उठीं। उसने बिना देर किए कंपनी के मुख्यालय को फैक्स भेजा, "यहाँ अपार संभावनाएँ हैं! यहाँ किसी के पास जूते नहीं हैं, इसलिए हम यहाँ लाखों जोड़ी जूते बेच सकते हैं। तुरंत नया स्टॉक भेजिए!" परिस्थितियाँ दोनों के लिए बिल्कुल समान थीं, लेकिन एक ने उसे समस्या मानकर हार मान ली और दूसरे ने उसी परिस्थिति में एक बड़ा अवसर ढूँढ निकाला। कठिनाइयां हर राह में आती हैं, जीतता वही है जो अभाव में भी अवसर तलाशने का सकारात्मक नजरिया रखता है।

डिवाइडर पर लोकतंत्र की नई पौध : हरियाली नहीं, होर्डिंग्स हैं जरूरी...! ट्रैफिक बाद में, बधाइयाँ पहले...

रोड डिवाइडर का जन्म ट्रैफिक को अनुशासन सिखाने के लिए हुआ था। उसका काम था—सड़क के बीच खड़े होकर दो दिशाओं से आने वाली गाड़ियों को अलग रखना, दुर्घटनाएं रोकना और यातायात को सुरक्षित बनाना। लेकिन हमारे शहर में भी डिवाइडर का काम कुछ और ही हो गया है। वह ट्रैफिक को नहीं, बधाई संदेशों को सुरक्षित रखने का काम कर रहा है और बधाई भी ऐसी कि जिसे देखकर लगता है कि शहर की सबसे बड़ी समस्या यातायात नहीं, शुभकामनाओं की कमी है।

किसी का जन्मदिन हो—डिवाइडर पर बधाई।

किसी की नियुक्ति हो—डिवाइडर पर बधाई।

किसी को नया पद मिला हो—डिवाइडर पर बधाई।

किसी का स्वागत करना हो—डिवाइडर पर बधाई।

और किसी को अपनी सार्वजनिक मौजूदगी दर्ज करानी हो, तो डिवाइडर सबसे सस्ता और सबसे बड़ा विज्ञापन बोर्ड है।

डिवाइडर अब सड़क का नहीं, सार्वजनिक पहचान का सहारा है। विडंबना देखिए, जिस डिवाइडर पर कभी पौधे लगने चाहिए थे, वहां अब मुस्कुराते हुए चेहरे उग आए हैं। हर कुछ दूरी पर एक नया चेहरा—शहर में विकास कम और बधाई देने वाले ज्यादा पैदा हो रहे हैं। जन्मदिन साल में एक बार आता है, लेकिन शुभचिंतकों की बधाई देखकर लगता है कि जन्मदिन रोज है। डिवाइडर पर संदेशा लगाने के लिए क्या नगर निगम की अनुमति ली जाती है ? यह सवाल पूछना ही शायद व्यवस्था को असहज कर देता है। कहीं-कहीं तो उन्हीं नगर निगम के महानुभावों को बधाई देते हुए होर्डिंग लगे दिखाई देते हैं, जिनकी जिम्मेदारी सार्वजनिक जगहों पर अवैध होर्डिंग और अतिक्रमण पर कार्रवाई करने की है। अब इसे संयोग कहें या व्यवस्था का नया संस्करण! जिसे निगरानी करनी है, उसी के सम्मान में निगरानी वाली जगह पर होर्डिंग लगा दिया गया।

फिर कार्रवाई कौन करेगा?

सड़क जनता के टैक्स से बनती है। डिवाइडर जनता के पैसे से बनता है। उसकी सफाई और रखरखाव पर सरकारी पैसा खर्च होता है। लेकिन सार्वजनिक संपत्ति को निजी प्रचार की दीवार समझने वालों की कमी नहीं है। आजकल बधाई के होर्डिंग्स में चेहरा इतना बड़ा रहता है कि पीछे सड़क छोटी दिखाई देती है। नाम इतना बड़ा कि पद पढ़ने के लिए चश्मा नहीं, दूरबीन चाहिए और नीचे बधाई देने वालों की ऐसी लंबी सूची कि देखकर लगता है कि पूरा शहर शुभकामनाओं की कतार में खड़ा है। असल में यह बधाई कम और सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज कराने की होड़ ज्यादा है।

कभी शहर में पेड़ लगाए जाते थे। अब होर्डिंग्स लगाए जाते हैं। कभी डिवाइडर हरियाली से सुंदर होते थे। अब उन पर मुस्कुराते हुए चेहरे हैं। कभी सार्वजनिक जगहें शहर की सुंदरता बढ़ाती थीं। अब वे सार्वजनिक प्रचार का माध्यम बन गई हैं और जनता? जनता उसी सड़क पर हॉर्न बजाती हुई निकल रही है, जिसके बीचों-बीच उसे रोज किसी न किसी चेहरे को बधाई देनी पड़ती है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि अगर नगर निगम की अनुमति के बिना डिवाइडर पर होर्डिंग्स लगाना गलत है, तो कार्रवाई क्यों नहीं होती ? अगर गलत नहीं है, तो फिर अनुमति की व्यवस्था किसलिए है ? अगर सार्वजनिक संपत्ति पर कोई भी प्रचार संदेश लगाया जा सकता है, तो फिर उसे सार्वजनिक संपत्ति कहने का औचित्य क्या है ? और अगर नियम सबके लिए बराबर हैं, तो फिर डिवाइडर पर चमकते चेहरे देखकर नियम अपना चश्मा क्यों उतार लेते हैं ? यह सिर्फ होर्डिंग्स का मामला नहीं है। यह उस मानसिकता का मामला है जिसमें सार्वजनिक जगह को निजी प्रचार की जगह समझ लिया गया है और प्रशासन को मूक दर्शक।

डिवाइडर को ट्रैफिक का प्रहरी होना था, लेकिन हमने उसे प्रचार का पोस्टर-बॉय बना दिया। कल को शायद एंबुलेंस भी डिवाइडर से रास्ता मांगती मिलेगी और फ्लेक्स मुस्कुराकर कहेगा—"पहले बधाई पढ़ लो, रास्ता बाद में मिलेगा।" यही हमारे शहर की सबसे बड़ी विडंबना है—सड़क पर गाड़ियां अपनी दिशा खोज रही हैं और डिवाइडर पर प्रचार अपना रास्ता।

कॉलम - खुरचन

द्वारा- हरिदास

नगर निगम की नजर बड़ी तेज है। सड़क किनारे गरीब का ठेला दिख जाता है। फुटपाथ पर सब्जी बेचता आदमी दिख जाता है। चाय की गुमटी दिख जाती है। फल का ठेला दिख जाता है। बस, नगर निगम की गाड़ी आती है और फरमान सुनाती है—"हटाओ, अतिक्रमण है!"

बेचारा ठेले वाला हाथ जोड़ता है—"साहब, यहीं से घर चलता है।"

जवाब आता है—"नियम सबके लिए बराबर हैं।"

गरीब अपना ठेला समेट लेता है। उसकी शाम की कमाई सड़क पर बिखर जाती है और वह अगले दिन फिर किसी कोने की तलाश में निकल पड़ता है। लेकिन उसी सड़क के डिवाइडर पर अगर विशाल होर्डिंग टंगा हो तो नगर निगम की नजर अचानक कमजोर पड़ जाती है। गरीब का अस्थायी कारोबार अतिक्रमण दिखाई देता है, लेकिन सार्वजनिक संपत्ति पर महीनों से टंगा स्थायी प्रचार शायद व्यवस्था की नजर में सिर्फ "सजावट" है।

अगर सड़क और सार्वजनिक जगह अतिक्रमण मुक्त रखनी है, तो नियम डिवाइडर से भी शुरू होना चाहिए। जिस हाथ में गरीब का ठेला हटाने की ताकत है, उसी हाथ में अवैध होर्डिंग उतारने का साहस भी होना चाहिए। क्योंकि अतिक्रमण तो अतिक्रमण है—चाहे वह किसी गरीब के ठेले का हो या किसी प्रभावशाली व्यक्ति के होर्डिंग का। वरना शहर में यही संदेश जाएगा कि नियम कमजोर के लिए लोहे की छड़ है और रसूखदार के लिए रबर की रस्सी।

छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा का 'नया सवेरा'

कौशल, अनुसंधान और रोजगार से गढ़ा जा रहा भविष्य

विष्णु वर्मा
सहायक जनसंपर्क अधिकारी

छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा की तस्वीर अब केवल किताबों और कक्षाओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह कौशल, तकनीक और रोजगार के नए आयाम गढ़ रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 की मूल भावना को आत्मसात करते हुए राज्य सरकार उच्च शिक्षा के परिदृश्य में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है। उद्देश्य स्पष्ट है—युवाओं को केवल डिग्री बांटना नहीं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर, हुनरमंद और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना। दूरस्थ अंचलों से लेकर बड़े शहरों के परिसरों तक, इस नई शैक्षणिक क्रांति की आहट साफ सुनी जा सकती है।

गुणवत्ता का 'मिशन मोड': सुदृढ़ मॉनिटरिंग और वित्तीय संबल

शिक्षा की गुणवत्ता में व्यापक और त्वरित सुधार लाने के लिए 'छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा मिशन' की नींव रखी गई है। इस मिशन के तहत राज्य के महाविद्यालयों का चयन कर प्रतिवर्ष उनके ढांचागत और शैक्षणिक उन्नयन के लिए विशेष राशि स्वीकृत की जाएगी। यह व्यवस्था केवल कागजों तक सीमित न रहे, इसके लिए एक मजबूत मॉनिटरिंग तंत्र भी तैयार किया गया है, जो यह सुनिश्चित करेगा कि स्वीकृत बजट का लाभ सीधे विद्यार्थियों तक पहुँचे।

उत्कृष्टता का नया पता: 36 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' महाविद्यालय

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप, राज्य के हर जिले में बहुसंकायी और अनुसंधान-केंद्रित शिक्षण संस्थानों की परिकल्पना को साकार किया जा रहा है। जिन महाविद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या 3000 से अधिक है और जिनका प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है, उन्हें 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' के रूप में विकसित किया जाएगा। ये 36 महाविद्यालय राज्य में शोध, नवाचार और उच्चस्तरीय अध्यापन के प्रमुख केंद्र बनकर उभरेंगे।

भविष्य की तकनीक और हुनर: स्वावलंबन की ओर बढ़ते कदम

बदलते दौर के साथ विद्यार्थियों को आधुनिक मांग के अनुरूप ढालने के लिए 'स्ववित्तीय पाठ्यक्रम नीति' लागू की जा रही है। इसके तहत स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए रोजगारपरक और तकनीकी पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, सेरीकल्चर (रेशम कीट पालन), फिशरीज और टसर टेक्नोलॉजी जैसे विषयों की पढ़ाई शुरू की जा रही है। आधुनिक तकनीक व उद्यमिता के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), साइबर सिक्योरिटी, वेब डिजाइनिंग, फूड प्रोसेसिंग, मशरूम कल्टीवेशन, फ्लोरीकल्चर और हर्बल कल्टीवेशन जैसे विषयों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। इन सभी के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ-साथ राज्य के कौशल विकास व तकनीकी विभागों के साथ MoU किए हैं, ताकि युवाओं को सीधे उद्योग और व्यावहारिक अनुभव से जोड़ा जा सके।

समावेशी विकास: वनांचल तक पहुँच और नए अवसर

शिक्षा का लाभ राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए दूरस्थ आदिवासी और वनांचल क्षेत्रों में नवीन महाविद्यालय खोले जा रहे हैं। इसके साथ ही औद्योगिक प्रतिष्ठानों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जा रहा है, जिससे युवाओं के लिए इंटर्नशिप और प्लेसमेंट के द्वार खुल सकें। शैक्षणिक क्षेत्र को और सशक्त बनाने के लिए चार वर्षीय बी.एड. (ITEP) और बी.पी.एड. जैसे एकीकृत व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का संचालन भी शुरू किया जा रहा है।

अनुभवी मार्गदर्शन और सुदृढ़ शिक्षक तंत्र

शिक्षा की गुणवत्ता तभी संभव है जब मार्गदर्शन देने वाले हाथ कुशल हों। इसी सोच के साथ उद्योग जगत और व्यावहारिक क्षेत्रों के विशेषज्ञों को 'प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस' के रूप में महाविद्यालयों से जोड़ने की योजना बनाई गई है। इसके साथ ही, उच्च शिक्षा विभाग में अध्यापन व्यवस्था को नई ऊर्जा देने के लिए शासकीय महाविद्यालयों में प्राध्यापक के 595 पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया को तेजी से पूर्ण किया जा रहा है।

एक उज्ज्वल भविष्य की नींव

छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा का यह कायाकल्प केवल नीतिगत बदलाव नहीं, बल्कि लाखों युवाओं के सपनों को उड़ान देने की एक ठोस पहल है। अनुसंधान, कौशल विकास, उद्योग-समन्वय और सुदृढ़ शिक्षक तंत्र के मेल से छत्तीसगढ़ तेज़ी से देश का एक प्रमुख 'एजुकेशन हब' बनने की ओर अग्रसर है।

भारत के DNA में विविधता में एकता

मैडिसन स्क्वायर में बोले मोहन भागवत

न्यूयार्क। अमेरिका के न्यूयार्क में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत के DNA में विविधता में एकता है. कई भाषाएं, धर्म और जीवन-शैली हैं, फिर भी एकता है. उन्होंने मैडिसन स्क्वायर गार्डन में आयोजित कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद को याद करते हुए कहा कि हर देश का एक मकसद और एक नियति होती है. भारत की नियति दुनिया को यह एहसास कराना है कि हम सब एक हैं.मोहन भागवत ने कहा, "भारत को क्या नियति मिली है? भारत का काम है इस विविधता में एकता को खुद महसूस करना और समय-समय पर दुनिया को भी इसका एहसास कराना."

प्रवासी भारतीयों को संदेश

मोहन भागवत ने प्रवासी भारतीयों से कहा कि अपनी कर्मभूमि के लिए काम करें, भारत के मूल्यों को नहीं भूलें, उसे अपनाएं. उन्होंने कहा कि हम हर चीज के लिए किसी न किसी के ऋणी हैं. हम दुनिया से लेते हैं. इसलिए हमें इसे वापस देना चाहिए. हम कितना कमाते हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है; हम कितना बांटते हैं, यह महत्वपूर्ण है.'यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन' नाम से आयोजित इस कार्यक्रम को 'अमेरिकन हिंदूज फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग' (एएचईएडी) ने मैडिसन स्क्वायर गार्डन में आयोजित किया. आयोजक ने दावा किया कि इस कार्यक्रम में 39 राज्यों और 853 शहरों के लोग शामिल हुए. 250 से अधिक स्टूडेंट्स अलग-अलग यूनिवर्सिटी के मौजूद थे. मोहन भागवत ने कहा, "आप एक आसान सा प्रयोग कर सकते हैं. जब आप दोपहर या रात का खाना खा रहे हों, तो किसी भूखे व्यक्ति को अपने सामने खड़ा होने दें और उसे भूखी नजरों से आपकी भरी हुई थाली को देखते रहने दें और उसकी नजरों से बचने या उसे वहां से भगाने के बजाय, बिना उसे एक भी निवाला दिए अपना खाना खाकर देखिए. आप ऐसा नहीं कर पाएंगे।

मोहन भागवत के बयान पर भड़के कपिल सिब्बल

राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने रविवार (30 अगस्त, 2026) को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत के अमेरिका के न्यूयॉर्क में दिए भाषण को लेकर उन पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जब कहा कि भारत एक-दूसरे के प्रति भावना रखता है और उसे महसूस करता है, तो वो क्या कहना चाह रहे थे? मैं सोच रहा था कि यह बात मोहन भागवत बोल रहे थे या फिर राहुल गांधी बोल रहे थे, क्योंकि यही बात राहुल गांधी हर वक्त बोलते रहते हैं. उन्होंने कहा कि संघ प्रमुख मोहन भागवत, जब आप न्यूयॉर्क में होते हैं, तो भारत एक-दूसरे के प्रति सहानुभूति दिखाता है, लेकिन जब आप दिल्ली में होते हैं, तब नहीं.

भागवत के मुसलमान वाले बयान को ओवैसी ने बताया 'पुरानी चाल'

संघ प्रमुख मोहन भागवत के न्यूयॉर्क में हुए कार्यक्रम के एक बयान पर अब AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है, उन्होंने इसे 'एक पुरानी चाल' कहकर तंज कसा है. मोहन भागवत ने अमेरिका में अपने एक कार्यक्रम में शनिवार को कहा था कि अगर कोई हिंदू यह सोचता है कि भारत में कोई मुसलमान नहीं होना चाहिए, तो वह हिंदू नहीं रहेगा.इसपर ओवैसी ने कहा है कि यह आरएसएस की पुरानी चाल है. कुछ बातें दुनिया के लिए होती है. कुछ अपने सदस्यों के लिए होती है. ओवैसी ने कहा, आरएसएस ने कभी भी अपने मुख्य विचारकों और लेखकों की बातों से किनारा नहीं किया है. वे मुसलमानों और दूसरे अल्पसंख्यकों के बारे में क्या कहते हैं यह बात जगजाहिर है।

यूपी में राशन दुकानों पर 18 रुपए किलो मिलेगी चीनी

बरेली। त्योहारों के बीच चीनी के बढ़ते दामों ने आम आदमी को चौंका दिया है। ऐसे में सितंबर महीने में

चीनी वितरण लोगों को थोड़ी राहत पहुंचाएगी। जिला पूर्ति विभाग की ओर से सस्ता गल्ला राशन की दुकानों पर हर महीने गेहूं चावल का वितरण किया जाता है। वहीं चीनी का वितरण तीन महीने में एक बार होता है। एक साथ तीन महीने की चीनी बीपीएल कार्ड धारकों को दी जाती है। ऐसे में सितंबर, अक्टूबर व नवंबर माह की चीनी एक साथ बीपीएल यानी बिलो पावर्टी लाइन के कार्ड धारकों को वितरित की जाएगी। जिला पूर्ति अधिकारी मनीष कुमार सिंह ने बताया कि जिले में कुल 99,687 बीपीएल कार्ड धारक हैं। सभी को एक साथ तीन महीने की चीनी 18 रुपये प्रति किलोग्राम के अनुसार वितरित की जाएगी। इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है। सभी राशन विक्रेता राशन का उठान करने में लगे हुए हैं। इसी के साथ चीनी का भी उठान किया जा रहा है। सामान्य बाजार में इन दिनों चीनी 65 से 70 रुपये प्रति किलो तक बेची जा रही है।

पाक सेना तक पहुंचा भारतीय सिम का जासूसी नेटवर्क

नई दिल्ली। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार साहिल और उसकी पत्नी समीरा से पूछताछ में जासूसी नेटवर्क की कई अहम कड़ियां सामने आ रही हैं। जांच एजेंसियों को शक है कि भारत से दुबई के रास्ते पाकिस्तान भेजे गए मोबाइल सिम कार्ड का इस्तेमाल वाट्सएप के जरिये भारतीयों और अन्य लोगों से संपर्क साधने के लिए भी किया जा रहा था। जांच में इन सिम कार्ड से एक्टिवेट किए गए कुछ वाट्सऐप अकाउंट की लोकेशन पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों के आसपास मिलने की बात सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक, साहिल और समीरा से जुड़े मामले में जिन आठ भारतीय सिम कार्ड को पाकिस्तान भेजे जाने की जानकारी एजेंसियों को मिली है, उनमें से कुछ का इस्तेमाल पाकिस्तान पहुंचने के बाद वाट्सएप अकाउंट एक्टिवेट करने में किया गया। जांच के दौरान सबसे अहम कड़ी यह सामने आई कि इन नंबरों पर वाट्सएप एक्टिवेशन के लिए जरूरी ओटीपी जिस समय प्राप्त हुआ, उस दौरान संबंधित सिम कार्ड पाकिस्तान में मौजूद था। इससे एजेंसियों को आशंका है कि सिम कार्ड को सीमा पार पहुंचाने के बाद उनका इस्तेमाल प्लानिंग के तहत किया गया। जांच में कुछ ऐसे वाट्सऐप अकाउंट की लोकेशन रावलपिंडी, लाहौर और कराची में सैन्य ठिकानों के आसपास मिलने की बात सामने आई है।

मार्च 2027 से सभी संस्थाओं में IST का पालन करना अनिवार्य

नई दिल्ली। अगले साल मार्च से भारत में सभी संस्थाओं को कानूनी, कमर्शियल, डिजिटल और प्रशासनिक कामों के लिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम (IST) का इस्तेमाल करना होगा। सरकार ने शनिवार को लीगल मेट्रोलॉजी (इंडियन स्टैंडर्ड टाइम) रूल्स, 2026 की घोषणा की। लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के तहत घोषित ये नियम गजट में छपने के 180 दिन बाद लागू होंगे, जिससे मार्च 2027 के आसपास से IST अनिवार्य हो जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने पर एक्ट के तहत जुर्माना लगाया जाएगा। यह नोटिफिकेशन सभी कानूनी, प्रशासनिक और आधिकारिक दस्तावेजों के लिए IST को अनिवार्य टाइम रेफरेंस बनाता है, जब तक कि विशेष रूप से छूट न दी गई हो। यह कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कानूनी कॉन्ट्रैक्ट और फाइनेंशियल कामकाज में भी आईएसटी को स्टैंडर्ड टाइम रेफरेंस बनाता है।

शुद्धिकरण विवादः राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत

नई दिल्ली। उत्तराखंड के हल्द्वानी में श्री राम सेना के अमित कुमार ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ कोतवाली में एक शिकायत दर्ज कराई है. अमित कुमार का आरोप है कि राहुल गांधी ने उनके खिलाफ जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है, इसलिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए. इस मामले पर हल्द्वानी पुलिस का कहना है कि अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है. पुलिस फिलहाल इस शिकायत की जांच कर रही है. यह विवाद तब शुरू हुआ जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की रैली के बाद श्री राम सेना के सदस्यों ने वहां 'शुद्धिकरण हवन' किया था, जिसके खिलाफ राहुल गांधी ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी. शुद्धिकरण विवाद पर श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास के सदस्य विनोद आर्य (शुद्धिकरण करान वाले) ने कहा, '...सनातन परंपरा के अनुयायी के रूप में, यह मेरा प्राथमिक अधिकार और कर्तव्य है कि मैं उस स्थान की स्वच्छता सुनिश्चित करूं जहां भगवान श्री राम की पूजा की जाती है और जहां विभिन्न धार्मिक समारोह आयोजित होते हैं. मैं स्वयं दलित हूं और इस गतिविधि के दौरान मेरे साथ दलित समुदाय के अन्य भाई भी थे.' आर्य ने आगे कहा, 'हमने निश्चित रूप से कुछ भी गलत नहीं किया. अब इस तथ्य के बावजूद कि हम दलित हैं, विपक्ष के नेता राहुल गांधी हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई और मामले दर्ज करने की मांग कर रहे हैं. हम राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना चाहते है।

PM मोदी ने ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री को दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताशकंद में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित की. उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री को याद करते हुए कहा कि हम उन्हें एक ऐसे महान नेता के रूप में याद करते हैं, जिनका देश के लिए अटूट समर्पण आज भी हर पीढ़ी को प्रेरणा देता है.

उज्बेकिस्तान के दो दिवसीय राजकीय दौरे के दूसरे दिन रविवार (30 अगस्त, 2026) को पीएम नरेंद्र मोदी सेंट्रल ताशकंद के शास्त्री स्ट्रीट के ग्रीन पार्क एरिया में स्थित पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादूर शास्त्री के स्मारक स्थल पर पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने पूर्व पीएम की प्रतिमा के आगे पुष्पांजलि अर्पित की. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शास्त्री जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक तस्वीर भी शेयर की.बता दें कि पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादूर शास्त्री की स्मृति और शांति की विरासत का सम्मान करने के लिए ताशकंद की स्थानीय सरकार की तरफ से सेंट्रल ताशकंद के एक सड़क का नाम शास्त्री स्ट्रीट रखा गया था और उनकी कांस्य की प्रतिमा भी स्थापित की गई थी.

राजनीति में आएंगे कॉकरोच जनता पार्टी के नेताः वांगचुक

नई दिल्ली। सीजेपी के संस्थापक सदस्यों के राजनीति में आने के सवाल पर एक्टिविस्ट सोनम वांगुचक ने कहा है कि सीजेपी के फाउंडर्स कोई संत नहीं है. उन्हें यकीन है कि उनकी कुछ न कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, जो कोई बुरी बात नहीं है. वांगचुक ने यह बयान प्रखर गुप्ता के साथ एक पॉडकास्ट में दिया है.

सोनम ने आगे कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर्स की अपनी राजनीतिक महत्वकांक्षाएं हैं. यह बात उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान महसूस की थी. इसके अलावा उन्होंने जोर देकर कहा कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखना गलत नहीं है. वह चाहेंगे कि ज्यादा युवा नेता राजनीतिक पार्टियों से जुड़ें या अपनी खुद की पार्टी बनाएं. वांगचुक ने कहा, 'जहां उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की बात है, तो मुझे लगता है कि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं. मैंने उन्हें काफी करीब से देखा है. मेरा मानना है कि निश्चित रूपसे उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं. शायद इसमें कुछ गलत भी नहीं है. उन्होंने मुझे यह नहीं बताया कि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं. यह मेरा उनके बारे में आकलन है।

'मेसी इवेंट के टिकट का पैसा मिलेगा वापस', बंगाल CM का ऐलान

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने लियोनेल मेसी वाले हंगामे का जिक्र करते बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि युवा भारती स्टेडियम में मेसी के अव्यवस्थित कार्यक्रम के लिए टिकट खरीदने वाले 33,000 प्रशंसकों को राज्य के खेल बजट से पैसा लौटाया जाएगा.विजार्ड ऑफ हॉकी मेजर ध्यानचंद की जयंती के मौके पर नबन्ना में आयोजित नेशनल स्पोर्ट्स डे के कार्यक्रम में उस घटना का जिक्र करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा, "मेसी के बहुत सारे फैन हैं. उन्होंने 4,000 और 6,000 रुपये के टिकट खरीदे थे. मेरी इच्छा है कि इन 33,000 खेल प्रेमियों को उनके पैसे वापस मिलें. मैंने इसके लिए अंदरूनी तौर पर प्रक्रिया शुरू कर दी है.

मुझे उम्मीद है कि मैं ऐसा कर पाऊंगा." बता दें कि लियोनेल मेसी 13 दिसंबर, 2025 को कोलकाता के युवा भारती स्टेडियम आए थे, लेकिन कार्यक्रम में काफी अव्यवस्था हुई थी. इस अव्यवस्था के लिए तृणमूल कांग्रेस सरकार के खेल मंत्री अरूप बिस्वास की अत्यधिक दखलंदाजी को जिम्मेदार ठहराया गया. हालांकि उस दिन स्टेडियम में मौजूद दर्शकों ने 4,000 रुपये और 6,000 रुपये के टिकटों के लिए पैसे वापसी की मांग की थी, लेकिन वह मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है.

BJP का जेन-जी के लिए खास प्लान! नितिन नवीन ने की बैठक, जमकर हुई मंत्रणा

नई दिल्ली। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने शनिवार को देशभर से बुलाए गए चुनिंदा 45 युवा नेताओं के साथ युवाओं के मुद्दे पर चर्चा की. बैठक में देश के युवाओं के साथ संवाद और भागीदारी को लेकर सारे प्रतिभागियों से राय मांगी गई और सभी प्रतिभागियों ने अपने-अपने राय और सुझाव दिए. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कुछ प्रतिभागियों ने कहा कि सभी युवाओं को एक ही श्रेणी में रखना ठीक नहीं है. साथ ही जेन-जी शब्द की जगह युवा और खास आयु वर्ग विशेष के लिए युवा शब्द के इस्तेमाल पर जोर दिया गया.

'सभी युवाओं को एक श्रेणी में रखना ठीक नहीं'

बैठक में शामिल कुछ प्रतिभागियों का यह भी कहना था कि देश के युवाओं को एक श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए बल्कि उनके बीच अलग अलग ग्रुप के युवा हो सकते हैं. सभी तरह के युवाओं के साथ अलग अलग ढंग से डील और संवाद पर जोर दिया गया. बैठक में शामिल एक केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि यह बस समय की बात है धीरे-धीरे सब ठीक हो जाता है. एक प्रतिभागी ने देश के युवाओं के साथ संवाद बढ़ाने की बात कही।

भीषण त्रासदी में बचे बुजुर्ग दंपत्ति ने बताई आपबीती

नेपाल बाढ़: एक साड़ी ने बचा ली 21 जिंदगियां

नई दिल्ली। नेपाल-तिब्बत बॉर्डर के पास सड़क पर बाढ़ का पानी आने और ऊपर से पत्थरों के गिरने के चलते बुजुर्ग तीर्थयात्रियों की जान सांसत में आ गई थी. इस दौरान ऊपर से लटकाई गई एक साड़ी कैसे सभी की जीवन-रेखा बन गई, ये किस्सा खुद उन्होंने सुनाया. शुक्रवार रात काठमांडू से चेन्नई पहुंचे 21 लोगों ने बताया कि कैसे उन्हें अपनी बस से निकलना पड़ा और बचाव का इंतजार करते हुए डेढ़ दिन बिताना पड़ा. हालांकि तीन बसों के ग्रुप में यात्रा कर रहे बाकी लोगों का शनिवार तक कोई पता नहीं चल पाया. चेन्नई के ही 49 तीर्थयात्रियों के एक दूसरे ग्रुप का भी कुछ पता नहीं चला. वेलाचेरी के मुरुगु नगर में रहने वाले नवु कबीरदास और उनकी पत्नी विजया भुवनेश्वरी ने कहा कि उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्हें नया जीवन मिला हो.

'बम फटने जैसी जोरदार आवाज'

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, बुजुर्ग दंपति कुंबाकोनम की एक एजेंसी द्वारा की गई व्यवस्था के तहत तीन बसों में रासुवा से यात्रा कर रहे 57 लोगों में शामिल था. उनके काफिले की दूसरी बस कीचड़ में फंसने के बाद मरम्मत के लिए थोड़ी देर रुकी थी. भुवनेश्वरी ने कहा कि उन कुछ मिनटों ने ही आखिरकार उनकी जान बचाई. कबीरदास ने कहा, "अचानक हमें बम फटने जैसी जोरदार आवाज सुनाई दी और वैन पर पत्थर गिरने लगे. फिर बाढ़ का पानी ऐसे तेजी से अंदर आया, जैसे कोई बांध खोल दिया गया हो." भुवनेश्वरी ने बताया कि उनके नेपाली ड्राइवर ने खतरा भांप लिया और सभी से बाहर निकलकर ऊपर की ओर भागने को कहा और खुद भी गाड़ी से भाग निकला. यात्री भी उसके पीछे-पीछे भागे. 21 लोगों से ज़्यादातर की उम्र 50 साल से अधिक थी, उन सभी को कीचड़ भरी ढलान से ऊंचाई पर चढ़ना पड़ा. वे बार-बार फिसलकर गिर रहे थे. ग्रुप की एक सदस्य पूंगोडी ने अपना स्वेटर पहना और साड़ी उतारकर नीचे मौजूद लोगों की तरफ लटका दी.

साड़ी ने बचाई सबकी जान

भुवनेश्वरी ने कहा, "हमने साड़ी और वहां मौजूद एक केबल को कसकर पकड़ा और ऊपर चढ़े. आखिर में एक महिला अकेले ऊपर नहीं चढ़ पा रही थी. हमने उससे कहा कि वह साड़ी को अपनी कमर पर बांध ले और हमारे ग्रुप के लोगों ने उसे पकड़कर सीधे ऊपर खींच लिया." कांचीपुरम के पंचायत यूनियन स्कूल की हेडमिस्ट्रेस सत्या ने बताया कि तीर्थयात्री सुबह 8 बजे चीनी इमिग्रेशन के लिए स्याब्रूबेसी से निकले थे. उनकी बस बीच में चल रही थी, तभी उन्होंने धूल का एक गुबार जैसा कुछ देखा. उन्होंने कहा, "पत्थर और कीचड़ सुनामी की लहर की तरह हमारी तरफ बढ़ रहे थे और उनकी ऊंचाई लगभग 70-80 फीट थी."

बिलावल भुट्टो यूरोप की राजकुमारी से करेंगे शादी?

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में एक खबर ने सोशल मीडिया पर जोर पकड़ लिया है, यह खबर वहां के राष्ट्रपति आसिफ अली

जरदारी के बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी से जुड़ी है. हालांकि, भुट्टो की पार्टी पीपल्स पार्टी ने इस मामले में दखल करते हुए, सारी अफवाहों को खारिज कर दिया है, जिसमें बताया गया है कि बिलावल भुट्टों एक यूरोपीय शाही परिवार से जुड़ने वाले हैं. कराची के मेयर और पीपीपी नेता मुर्तजा वहाब ने पार्टी चेयरमैन की सगाई और शादी की खबरों को गलत और बेबुनियाद करार दिया है. वहाब का यह स्पष्टीकरण शनिवार देर रात एक्स पर पोस्ट करते हुए आया है. उन्होंने भी तब इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें ऐसी खबरें फैलने लगी थीं कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के 38 साल के बेटे बिलावल किसी यूरोपीय परिवार में शादी करने की तैयारी कर रहे हैं. यह खबरें सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल थीं. इसमें कहा गया था कि पाक राष्ट्रपति अपने बेटे की शादी की तारीफ तय करने के लिए लिकटेंस्टीन गए थे, यह स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच स्थित एक छोटा सा स्वतंत्र देश है.

साप्ताहिक शहर सत्ता
हम दिखाएंगे आईना...

नेपाल को एडवांस बिजली देगा भारत, बाढ़ से ठप हुए पावर प्लांट

नई दिल्ली। नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ ने बिजली उत्पादन को बड़ा झटका दिया है. कई जलविद्युत परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं, जिससे वहां करीब 550 मेगावाट (mw) बिजली उत्पादन क्षमता में कमी आई है. ऐसे मुश्किल वक्त में भारत नेपाल की मदद करने के लिए आगे आया है. भारत अब नेपाल को जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त बिजली उपलब्ध कराने की तैयारी कर रहा है, ताकि वहां बिजली आपूर्ति को सामान्य तौर पर बनाए रखा जा सके. भारत के बिजली मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक, नेपाल ने बाढ़ के कारण हुई बिजली उत्पादन में कमी को देखते हुए भारत से अतिरिक्त बिजली आयात की मंजूरी को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया है. नेपाल की मांग के अनुसार, भारत जरूरत पड़ने पर उसे बिजली उपलब्ध कराएगा. 26 अगस्त 2026 को त्रिशुली और लेंडे खोला नदी बेसिन में अचानक आई बाढ़ से नेपाल के कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ. इस के कारण कई जलविद्युत परियोजनाओं का काम भी प्रभावित हुआ और बिजली उत्पादन में करीब 550 मेगावाट की कमी आई.

मोहम्मद अब्बास ने पांच विकेट लेकर रचा इतिहास

नई दिल्ली। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद अब्बास ने लॉर्ड्स में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट की दूसरी पारी में 5 विकेट लेकर कई रिकार्ड्स बनाए. इंग्लैंड की दूसरी पारी 208 रनों पर सिमट गई, जिसके बाद पाकिस्तान को जीतने के लिए 389 का लक्ष्य मिला. हालांकि बाबर आजम एंड टीम की शुरुआत खराब रही, टीम ने 14 के स्कोर पर अपना तीसरा विकेट गंवा दिया था. मोहम्मद अब्बास ने दूसरी पारी में पहला विकेट ओपनर इमिलिओ गै का लिया था, जिन्हें उन्होंने एलबीडबल्यू आउट किया था. इसके बाद उन्होंने हैरी ब्रूक (34), डेन लॉरेंस (54), जेमी स्मिथ (7) को आउट किया. ओली रॉबिंसन (8) के रूप में उन्होने पारी का नौवां और अपना पांचवां विकेट लिया. लॉर्ड्स टेस्ट की एक पारी में 5 विकेट लेने वाले मोहम्मद अब्बास पाकिस्तान के 7वें गेंदबाज बन गए हैं. उनसे पहले खान मोहम्मद, मुदस्सर नजर, वकार यूनिस, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद आमिर और यासिर शाह ऐसा कर चुके हैं.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से कगिसो रबाडा बाहर

नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज से तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा बाहर हो गए हैं. रबाडा को दाहिनी हैमस्ट्रिंग में गंभीर चोट (ग्रेड-3 टियर) लगी है. ऐसे में रबाडा अब करीब दो महीने तक क्रिकेट से दूर रहेंगे. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज से पहले कगिसो रबाडा का चोटिल होना दक्षिण अफ्रीका के लिए बड़ा झटका है. कगिसो रबाडा की घरेलू टीम 'लायंस' के गेंदबाजी कोच और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज एलन डोनाल्ड ने कहा कि मेडिकल जांच के बाद उन्हें इस हाई-प्रोफाइल सीरीज से पूरी तरह बाहर कर दिया गया है।

IPL 2027 में नहीं दिखेंगे 3 दिग्गज क्रिकेटर

पहला भारतीय सेंचुरियन रह सकता है अनसोल्ड

इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी सीजन में फैंस 3 ऐसे खिलाड़ियों को मिस करेंगे, जो पहले संस्करण से लेकर पिछले संस्करण तक खेल रहे थे. इसमें एक संन्यास ले चुका प्लेयर है, एक अनसोल्ड रह सकता है और एक सीजन से पहले संन्यास की घोषणा कर सकता है. बता दें कि सभी फ्रेंचाइजी IPL 2027 के लिए होने वाले ऑक्शन को लेकर अपनी तैयारियां कर रही हैं. कई ट्रेड पर विचार कर रही हैं तो कई उन खिलाड़ियों को चिन्हिंत कर रही हैं, जिन्हे वह खरीदना चाहती हैं. IPL 2027 से पहले एक सबसे बड़ी ट्रेड डील तो हो चुकी है. ऋषभ पंत वापस दिल्ली कैपिटल्स में लौट गए हैं, जिन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड रकम के साथ खरीदा था. दिल्ली ने उनके बदले कुलदीप यादव को दिया है. अब हार्दिक पांड्या सुर्खियों में हैं, जिनको लेकर माना जा रहा है कि वह मुंबई इंडियंस से अलग हो सकते हैं.

अजिंक्य रहाणे

पिछले साल कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए कप्तानी करने वाले अजिंक्य रहाणे ने इसी साल 30 जुलाई को इंटरनेशनल क्रिकेट और क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है. फैंस उन्हें IPL 2027 में मिस करेंगे, जो आईपीएल के पहले सीजन से खेल रहे हैं. उन्होंने मुंबई इंडियंस के साथ शुरुआत कि थी, फिर राजस्थान रॉयल्स में गए. उन्होंने राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स के लिए 2 साल खेला, फिर राजस्थान में लौट आए. दिल्ली कैपिटल्स, केकेआर के लिए खेलने के बाद वह चेन्नई सुपर किंग्स में आए और फिर केकेआर में लौट आए. उन्होंने IPL में 6 टीमों के लिए 212 मैच खेले, जिनमें खेली 197 पारियों में 5367 रन बनाए.

एमएस धोनी

चेन्नई सुपर किंग्स को अपनी कप्तानी में 5 बार चैंपियन बना चुके एमएस धोनी भी शायद अगले साल खेलते हुए न दिखे. हालांकि वह पिछले साल भी नहीं खेले, लेकिन इसमें नहीं खेलने का कारण उनकी फिटनेस था और अब वह संन्यास ले सकते हैं. धोनी 2008 से 2015 तक चेन्नई के लिए खेले, 2015 और 2016 में राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स के लिए खेलने वाले धोनी 2018 में फिर सीएसके में लौट आए. उन्होंने आईपीएल में 278 मैचों में खेली 242 पारियों में 5439 रन बनाए.

मनीष पांडे

आईपीएल के पहले सीजन से खेल रहे मनीष पांडे को भी फैंस अगले साल मिस कर सकते हैं, जो अभी कोलकाता नाइट राइडर्स में शामिल हैं. उन्होंने पिछले सीजन केकेआर के लिए सिर्फ 6 मैच खेले, जिनकी 2 पारियों में 70 रन बनाए. 2025 में भी उन्होंने सिर्फ 3 और 2024 में सिर्फ 1 मैच खेला. अब IPL 2027 के लिए होने वाले ऑक्शन से पहले केकेआर उन्हें रिलीज कर सकती है.

मोहम्मद शमी ने रचा इतिहास, पूरे किए 900 विकेट

नई दिल्ली। मोहम्मद शमी ने दलीप ट्रॉफी सेमीफाइनल के पहले दिन इतिहस रचा, उन्होंने ऐसा मुकाम हासिल किया जो इससे पहले सिर्फ 5 ही भारतीय गेंदबाज कर पाए. बता दें कि शमी ईस्ट जोन के लिए खेल रहे हैं, जिसका सेमीफाइनल मुकाबला सेंट्रल जोन के साथ आज से शुरू हुआ. शमी आज 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी की कप्तानी में खेले. हालांकि इस टीम के कप्तान ईशान किशन हैं, लेकिन पहले दिन चोट के कारण उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा. उनकी गैरमौजूदगी में वैभव ने कमान संभाली, जो टीम में बतौर उपकप्तान चुने गए हैं. दलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल में ईस्ट जोन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. सेंट्रल जोन की पहली पारी 266 रनों पर सिमट गई, अंतिम विकेट के साथ पहले दिन के खेल की समाप्ति की घोषणा भी हुई. आर्यन जुयाल ने 46 रन बनाए, जो वैभव द्वारा लिए गए रिव्यू के चलते आउट हुए. दरअसल अंपायर ने उन्हें नॉट-आउट दिया था, लेकिन तब कप्तानी कर रहे वैभव ने रिव्यू ले लिया था।

2027 वनडे वर्ल्ड कप की टीम इंडिया में आएगा 23 साल का स्टार!

नई दिल्ली। 2026 हॉकी वर्ल्ड कप में मेजबान नीदरलैंड ने भारतीय टीम को हरा दिया है. नीदरलैंड ने 3-1 से भारत को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. वहीं इस हार के बाद भारतीय टीम अब सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गई है.

टीम इंडिया के लिए यह मैच करो या मरो वाला था, क्योंकि अंतिम 4 में जगह बनाने के लिए भारतीय टीम को हर हाल में यह मैच जीतना था. हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी वाली भारतीय टीम को अब दूसरे दौर का आखिरी मैच सोमवार को अर्जेंटीना से खेलना है. इसके बाद टीम पांचवें से आठवें स्थान के क्लासीफिकेशन मुकाबले खेलेगी.

भारत के लिए मैच में एकमात्र गोल कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 52वें मिनट में किया. नीदरलैंड के लिये डुको टेलगेनकेम्प, येप होडेमेकर्स और वान डैम यिप ने गोल दागे. इस जीत के साथ डच टीम सेमीफाइनल में जगह बनाने में कामयाब रही. पहले दौर में इंग्लैंड से हारने वाली भारतीय टीम दूसरे दौर में कोई अंक लेकर नहीं आई थी. अब अर्जेंटीना को हराने के बाद भी उसके तीन ही अंक होंगे, जिससे उसके अंतिम चार में पहुंचने की उम्मीदें खत्म हो गई है।

श्रीलंका से छीनी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी!

नई दिल्ली। श्रीलंका से जुड़ी एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है. इस खबर से श्रीलंका क्रिकेट को तगड़ा झटका लगेगा. दरअसल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने श्रीलंका से चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी छीन ली है. अब किसी नए देश को इस मेगा इवेंट की मेजबानी सौंपी जाएगी. एक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है.

आईसीसी ने श्रीलंका से पहली बार होने वाली महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी का अधिकार छीन लिया है. नए मेजबान देश को लेकर फैसला आईसीसी की अगली बैठक में लिया जाएगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह फैसला तब लिया गया जब आईसीसी ने तय किया कि वो श्रीलंका में टूर्नामेंट की मेजबानी के साथ आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) को सरकार द्वारा नियुक्त एक अंतरिम प्रशासन चला रहा है.

बता दें कि महिला क्रिकेट में अगले साल पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी खेली जाएगी, जिसकी शुरुआत 14 फरवरी से होगी, जबकि फाइनल मुकाबला 28 फरवरी 2027 को खेला जाना है. इस टूर्नामेंट में कुल छह टीमें हिस्सा लेंगी.

भारत से बार-बार पेट्रोल क्यों मांग रहा रूस?

नई दिल्ली। रूस दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल निर्यातकों में शामिल है, लेकिन यूक्रेन के लगातार ड्रोन हमलों ने उसकी घरेलू ईंधन सप्लाई को काफी नुकसान पहुंचाया है. हालात ऐसे हो गए हैं कि रूस को अपनी जरूरत पूरी करने के लिए दूसरे देशों से पेट्रोल आयात करना पड़ रहा है. इसी बीच भारत रूस के लिए पेट्रोल सप्लाई करने वाले प्रमुख देशों में शामिल हो गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, पिछले दो महीनों में भारतीय रिफाइनरियों ने रूस को करीब 10 लाख बैरल गैसोलीन (Petrol) की आपूर्ति की है. माना जा रहा है कि यह ईंधन रूस से आयात किए गए कच्चे तेल से ही तैयार किया गया हो सकता है. दरअसल, यूक्रेन ने रूस के कई तेल डिपो, टर्मिनल और रिफाइनरियों को निशाना बनाकर कई बार ड्रोन हमले किए हैं. इन हमलों के कारण रूस की घरेलू ईंधन उत्पादन क्षमता को बड़ा नुकसान हुआ है, जिससे वहां पेट्रोल की काफी ज्यादा कमी पैदा हो गई है. घरेलू मांग और सप्लाई के बीच संतुलन बनाने के लिए रूस को पेट्रोल आयात करना पड़ा।

होम लोन हुआ सस्ता, 7% की ब्याज दर पर मिल रहा

नई दिल्ली। अगर आप घर खरीदने के लिए होम लोन लेने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. अगस्त 2026 में कुछ बैंक 7% की शुरुआती ब्याज दर पर होम लोन ऑफर कर रहे हैं. पब्लिक सेक्टर के बैंक इस मामले में सबसे आगे हैं. पैसा बाजार के 26 अगस्त 2026 तक के आंकड़ों के हिसाब से, बैंक ऑफ महाराष्ट्रा और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 7% की शुरुआती दर पर होम लोन दे रहे हैं. बैंक ऑफ इंडिया में होम लोन की ब्याज दर 7.10% से शुरू हो रही है. वहीं UCO बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शुरुआती दर 7.15% है. कैनरा बैंक में 30 लाख रुपये तक के लोन पर दर 7.25% से शुरू होती है, जबकि 75 लाख रुपये से ज्यादा के लोन पर ये 7.15% तक आ जाती है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शुरुआती ब्याज दर सभी लोन स्लैब में 7.25% है.

प्राइवेट बैंकों में क्या है ऑफर?

प्राइवेट बैंकों में साउथ इंडिया बैंक सबसे कम 7.25% की शुरुआती ब्याज दर पर होम लोन दे रहा है. कर्नाटका बैंक में ये 7.48% और ICICI बैंक में 7.55% से शुरू है. HDFC Bank की शुरुआती दर 7.75% है, जबकि Axis Bank 8% से होम लोन दे रहा है. RBL Bank की शुरुआती दर 9% है.हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां भी कम ब्याज दर पर होम लोन दे रही हैं. LIC हाउसिंग फाइनेंस की दर 7.15% से शुरू होती है. बजाज हाउसिंग फाइनेंस 7.25 % और ICICI होम फाइनेंस 7.50% से होम लोन दे रहा है. PNB हाउसिंग फाइनेंस में 30 लाख रुपये तक के लोन की शुरुआती दर 7.75% है.

शुरुआती दर देखकर फैसला नहीं करें

लेकिन, ad में दिखाई जाने वाली सबसे कम ब्याज दर हर कस्टमर को मिले, ये जरूरी नहीं है. बैंक ब्याज दर फिक्स करते समय क्रेडिट प्रोफाइल, इनकम, नौकरी, लोन की रकम और कस्टमर की लायक चीजों को देखते हैं. इसलिए लोन लेने से पहले अलग अलग बैंकों के ऑफर्स की तुलना करना जरूरी है.सिर्फ ब्याज दर ही नहीं, बल्कि प्रोसेसिंग फीस, दूसरे चार्ज और पूरे लोन की समय में चुकाए जाने वाले कुल ब्याज को भी ध्यान में रखना चाहिए. लंबे समय के बड़े होम लोन में ब्याज दर का छोटा सा अंतर भी कुल पेमेंट में बड़ा फर्क डाल सकता है.

जानिए बैंक के जरूरी नियम

गलत खाते में चले गए पैसे तो कैसे मिलेगा रिफंड?

नई दिल्ली। डिजिटल पेमेंट के दौर में पैसे ट्रांसफर करना बेहद आसान हो गया है, लेकिन एक छोटी सी गलती पैसे को गलत अकाउंट तक पहुंचा सकती है. अकाउंट नंबर या IFSC कोड डालते समय हुई गलती के वजह से अगर पैसा किसी दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में चला जाए, तो घबराने के बजाय तुरंत बैंक से संपर्क करना चाहिए. समय पर शिकायत करने से रकम वापस लेने की प्रोसेस शुरू की जा सकती है. गलत अकाउंट में पैसे पहुंचने का पता चलते ही अपने बैंक को इसकी जानकारी दे. आप कस्टमर केयर, ईमेल या बैंक शाखा के जरिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं. बेहतर होगा कि जल्द से जल्द शाखा जाकर ब्रांच मैनेजर से भी बात करें. शिकायत करते समय ट्रांजैक्शन की तारीख और समय, पैसा, अपना अकाउंट नंबर, गलत अकाउंट की जानकारी और UTR या Transaction ID जैसी जरूरी डिटेल दे. बैंक से मिलने वाला शिकायत नंबर या रसीद संभालकर रखना भी जरूरी है.

दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में पहुंच गया पैसा

अगर पैसा किसी दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में पहुंच चुकी है, तो आपका बैंक दूसरे बैंक और अकाउंट होल्डर से संपर्क करके पैसे वापस कराने की प्रोसेस शुरू कर सकता है. अगर जिसके अकाउंट में पैसा गया है वह लौटाने के लिए तैयार हो जाता है, तो बैंक की प्रोसेस के अनुसार पैसा वापस मिल सकता है. लेकिन अगर अकाउंट होल्डर रकम लौटाने से इनकार करता है, तो मामला पेचीदा हो सकता है. ऐसी हालत में बैंक में लिखित शिकायत के बाद कानूनी प्रोसेस अपनाने की जरूरत पड़ सकती है.अगर अकाउंट नंबर या IFSC में गलती के वजह से बैंक उस अकाउंट को पैसा क्रेडिट नहीं कर पाता, तो कुछ मामलों में ट्रांजैक्शन फेल होकर पैसा वापस आपके अकाउंट में आ सकता है. लेकिन, यह ट्रांजैक्शन की हालात और बैंकिंग सिस्टम पर निर्भर करता है. अगर रकम किसी वैलिड बैंक अकाउंट में सही तरीके से जमा हो गई है, तो उसे वापस आने में समय लग सकता है.

ऑनलाइन पेमेंट करते समय रखें सावधानी

पैसे भेजने से पहले अकाउंट नंबर और IFSC कोड दोबारा जांचें. किसी नए व्यक्ति को पेमेंट करते समय जल्दबाजी नहीं करें. बड़ी रकम भेजने से पहले छोटी रकम ट्रांसफर करके जानकारी चेक की जा सकती है. UPI से पैसे भेजते समय सामने वाले का नाम जरूर चेक करें और जिन लोगों को बार बार पैसे भेजते हैं, उनकी सही जानकारी सेव कर लें. अगर पैसे गलत अकाउंट में चले जाएं, तो UTR या Transaction ID, SMS और बैंक स्टेटमेंट संभालकर रखें और तुरंत बैंक में शिकायत करें.

कमाई के मामले में दिल्ली देश में नंबर 1

नई दिल्ली। दिल्ली सिर्फ राजनीति और कारोबार का केंद्र ही नहीं है, बल्कि राज्यों की वित्तीय स्थिति के मामले में भी काफी मजबूत है. वित्त वर्ष 2024-25 के बजट अनुमानों के अनुसार दिल्ली देश में सबसे ज्यादा अपने स्रोतों से टैक्स जुटाने वाले राज्यों में सबसे आगे है. दिल्ली के टोटल टैक्स में उसके अपने स्रोतों से आने वाले टैक्स की हिस्सेदारी करीब 91.6 फीसदी है.इसका मतलब है कि दिल्ली सरकार की आय का बहुत बड़ा हिस्सा राज्य के अपने टैक्स और गैर-टैक्स से आ जाता है. उसे अपने खर्च और विकास योजनाओं के लिए दूसरे राज्यों के मुकाबले में केंद्र से मिलने वाले पैसों पर कम निर्भर रहना पड़ता है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, FY25 के बजट अनुमानों में दिल्ली के टोटल टैक्स में स्वयं का स्रोत टैक्स की हिस्सेदारी 91.6 फीसदी है. ये देश के सभी राज्यों में सबसे ज्यादा है, नंबर 1 पर ही है. स्वयं का स्रोत टैक्स में खास तौर से सरकार द्वारा अपने स्तर पर जुटाया गया टैक्स और नॉन-टैक्स रेवेन्यू शामिल होता है. यानी राज्य को अपनी आय के लिए दूसरे स्रोतों से मिलने वाले फंड पर ज्यादा निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ती है. दिल्ली की मजबूत टैक्स स्थिति के पीछे राजधानी का बड़ा बाजार, कारोबार, रियल एस्टेट और दूसरे इनकम सोर्स हैं.

देश में बढ़ेगी ऊर्जा स्टोरेज क्षमता, SECL विकसित करेगा 700 मेगावाट सौर ऊर्जा

शहर सत्ता/रायपुर। शहर सत्ता/रायपुर/बिलासपुर। देश में सौर और पवन ऊर्जा का उत्पादन बढ़ने के साथ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस) का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की राष्ट्रीय विद्युत योजना के अनुसार, वर्ष 2030 तक देश में करीब 208 गीगावाट घंटे की बैटरी स्टोरेज क्षमता विकसित हो जाएगी। यह क्षमता अतिरिक्त बिजली को संग्रहित कर जरूरत के समय उपलब्ध कराने में मदद करेगी। इससे 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति के साथ ग्रिड की स्थिरता भी बढ़ेगी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, देश में एक मेगावाट घंटे से अधिक क्षमता वाली 798 मेगावाट घंटे की बैटरी स्टोरेज परियोजनाएं स्थापित हो चुकी हैं। वहीं, 35.8 गीगावाट घंटे की परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। छत्तीसगढ़ में भी 120 मेगावाट घंटे की क्षमता स्थापित की जा चुकी है। यह परियोजना राजनांदगांव में है। इधर, कोल इंडिया की सहायक कंपनी एसईसीएल ने भी ग्रीन एनर्जी पोर्टफोलियो बढ़ाने की तैयारी की है। कंपनी ने वर्ष 2028-29 तक 700 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत ग्राउंड माउंटेड, रूफटॉप और फ्लोटिंग सोलर परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया है। इससे परियोजनाओं के लिए अपेक्षाकृत सस्ती वित्तीय सहायता मिलने का रास्ता खुला है। वायबिलिटी गैप फंडिंग जैसी योजनाओं के जरिए भी इस क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की कोशिश की जा रही है।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने 93 करोड़ के कार्यों का किया भूमिपूजन

शहर सत्ता/रायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने आज जशपुर कम्युनिटी हॉल में 93 करोड़ 91 लाख 98 हजार रुपए के विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। इनमें अमृत मिशन 2.0 के तहत 86 करोड़ 99 लाख 21 हजार रुपए की पेयजल योजना और स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के अंतर्गत 6 करोड़ 92 लाख 77 हजार रुपए लागत के एसटीपी का निर्माण शामिल हैं। उन्होंने कार्यक्रम में जशपुर नगर के विकास के लिए 4 करोड़ 68 लाख रुपए के नए कार्यों की भी घोषणा की। इनमें जशपुर नगर पालिका कार्यालय के सामने शॉपिंग कॉम्पलेक्स के निर्माण के लिए एक करोड़ 40 लाख रुपए, देशपांडे पार्क एवं तालाब सौंदर्यीकरण के लिए डेढ़ करोड़ रुपए, मटन मार्केट के लिए एक करोड़ 48 लाख रुपए और शव वाहन के लिए 30 लाख रुपए की राशि शामिल है।

UCC को लेकर मुस्लिम समाज की बैठक 1 सितंबर को

शहर सत्ता/रायपुर। राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (UCC) कानून लागू करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है और इसके लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति को सुझाव देने के लिए रायपुर मुस्लिम समाज की ओर से एक दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया है। यह जानकारी छ.ग. राज्य वक्फ बोर्ड (कैबिनेट मंत्री दर्जा) के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने दी है। मुस्लिम समाज की यह बैठक 01 सितंबर 2026, मंगलवार को स्थान- गुरु घासीदास ऑडिटोरियम, कार्यालय छ.ग. राज्य वक्फ बोर्ड के सामने, कलेक्ट्रेट चौक, रायपुर में आयोजित की जाएगी। बैठक में मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवियों द्वारा दिए गए सुझावों को एकत्रित किया जाएगा। इसके लिए रायपुर की समस्त मस्जिदों में जुमा को ऐलान के माध्यम से सूचना दी गई है।

छत्तीसगढ़ में 3 साल बाद एक मंच पर खेल सम्मान

21 खेलों में 325 अलंकरण, किक बॉक्सिंग-कुडो का दबदबा; रायपुर व्यक्तिगत खेलों में आगे

शहर सत्ता/रायपुर। शनिवार को पं. दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में राज्य खेल अलंकरण समारोह-2026 आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय मुख्य अतिथि रहे, जबकि उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने अध्यक्षता की। केंद्रीय मंत्री तोखन लाल साहू, डॉ. रमन सिंह समेत प्रदेश के कई मंत्री और विधायक भी कार्यक्रम में शामिल हुए।

इस बार समारोह में 2023-24, 2024-25 और 2025-26 यानी तीन साल के राज्य खेल अलंकरण एक साथ दिए गए। राज्य खेल अलंकरण में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों, कोचों और टीमों को अलग-अलग श्रेणियों में सम्मानित किया गया। तीन साल का सम्मान एक साथ दिए जाने से लंबे समय से लंबित सम्मान भी दिए गए। 2025-26 के नगद पुरस्कारों में 21 खेलों के खिलाड़ियों और प्रतिभागियों को कुल 325 पुरस्कार दिए गए। इनमें किक बॉक्सिंग और कुडो के पुरस्कार सबसे ज्यादा रहे। वहीं एथलेटिक्स में 2 और बैडमिंटन में 1 पुरस्कार दिया गया। टीम प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन करने वाली टीमों को मुख्यमंत्री ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। समारोह में पैरा खेलों के खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया।

21 खेलों के खिलाड़ियों को 325 पुरस्कार

2025-26 के नगद पुरस्कारों में 21 खेलों के खिलाड़ियों और अन्य प्रतिभागियों को कुल 325 पुरस्कार दिए गए। इनमें किक बॉक्सिंग और कुडो के खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा पुरस्कार मिले। वहीं एथलेटिक्स में 2 और बैडमिंटन में 1 पुरस्कार दिया गया। अलग-अलग खेलों में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर ये पुरस्कार दिए गए।

दुर्ग-भिलाई और बिलासपुर का दबदबा

अलंकरण सूची में दुर्ग-भिलाई के खिलाड़ियों ने हॉकी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, कुश्ती, नेटबॉल और मास्टर्स बैडमिंटन जैसे खेलों में जगह बनाई। हॉकी में भूमिका उपाध्याय, टेबल टेनिस में काजल, बैडमिंटन में संगीता राजगोपाल, कुश्ती में गामा यादव और वेटलिफ्टिंग में भूपेंद्र कुमार गडे का नाम शामिल है। वहीं, बिलासपुर के खिलाड़ियों ने शूटिंग, तैराकी, तीरंदाजी समेत कई खेलों में अच्छा प्रदर्शन किया। सीता साहू, शशांक मसीह, स्वाती साहू, संकेत सामुएल और अजित्या सिंह सहित कई खिलाड़ियों को अलंकरण सूची में शामिल किया गया है।

पैरा खिलाड़ियों को भी मिला सम्मान

खेल अलंकरण में पैरा खिलाड़ियों और पैरा खेलों को भी शामिल किया गया। सूची में पैरा एथलेटिक्स, पैरा फेंसिंग, पैरा जूडो, पैरा तैराकी और व्हीलचेयर फेंसिंग के खिलाड़ी शामिल रहे। महासमुंद के सुखदेव ने 100 मीटर और 1500 मीटर में राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। बिलासपुर की सीता साहू और स्वाती साहू ने व्हीलचेयर फेंसिंग में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीते हैं। पैरा जूडो और पैरा तैराकी के खिलाड़ियों को भी उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया।

तीन साल के खेल अलंकरण एक साथ

राज्य खेल अलंकरण सामान्य तौर पर हर साल राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों, कोचों और टीमों को दिए जाते हैं। इस बार 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के तीन वर्षों के लंबित अलंकरण एक साथ दिए गए। पुरस्कारों में शहीद राजीव पांडेय पुरस्कार, शहीद कौशल यादव पुरस्कार, वीर हनुमान सिंह पुरस्कार, शहीद विनोद चौबे सम्मान और शहीद पंकज विक्रम सम्मान शामिल हैं।

राज्यपाल ने किया शिक्षकों, मेधावी विद्यार्थियों और रोजगार प्राप्त युवाओं का सम्मान

शहर सत्ता/रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका बलौदाबाजार विकासखंड के ग्राम चाम्पा स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित लोकार्पण एवं सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने विद्यालय के नवनिर्मित सभाकक्ष का लोकार्पण किया। साथ ही, वरिष्ठ शिक्षकों, 10वीं व 12वीं के मेधावी छात्रों, पीएटी में चयनित विद्यार्थियों और 'हम होंगे कामयाब' योजना के तहत रोजगार प्राप्त 9 युवाओं को सम्मानित किया।

जुनून और कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी- राज्यपाल

समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल रमेन डेका ने कहा कि नवनिर्मित सभाकक्ष से विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारने के लिए सांस्कृतिक और ज्ञानवर्धक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने शिक्षक-छात्र संबंधों की प्रगाढ़ता पर जोर देते हुए कहा कि शिक्षकों को अपने आचरण से छात्रों का रोल मॉडल बनना चाहिए। छात्रों को संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए जुनून पैदा करें और उसे हकीकत में बदलने के लिए निरंतर कड़ी मेहनत करें। नई शिक्षा नीति का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि यह नीति कौशल विकास और विषय विशेषज्ञता हासिल करने में सहायक है।

डिजिटल तकनीक का संतुलित उपयोग जरूरी

राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि मोबाइल और सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग पर चिंता व्यक्त करते हुए राज्यपाल ने छात्रों से अपील की कि वे तकनीक का इस्तेमाल केवल आवश्यक कार्यों के लिए ही करें। सोशल मीडिया और एआई (AI) सुविधाजनक जरूर हैं, लेकिन इनका अत्यधिक उपयोग आत्ममंथन और सृजनात्मक को कम कर देता है। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने राज्यपाल के आगमन को चाम्पा गांव के लिए ऐतिहासिक बताया। उन्होंने अपने स्कूली दिनों को याद करते हुए कहा कि शिक्षक न केवल शिक्षा देते हैं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी का बोध भी कराते हैं।

खेल अंतिम क्षण तक लड़ने का साहस देता हैः कुलपति प्रो. दयाल

शहर सत्ता/रायपुर। खेल केवल शारीरिक और मानसिक विकास का माध्यम नहीं है, बल्कि यह विपरीत परिस्थितियों में अंतिम क्षण तक संघर्ष कर जीत हासिल करने की अदम्य क्षमता का निर्माण करता है। उक्त उद्गार कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर के कुलपति प्रो. डॉ. मनोज दयाल ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि खेलों से खेल भावना, टीम भावना, नेतृत्व क्षमता, साहस, धैर्य, उत्साह, सकारात्मकता और आपसी समन्वय जैसे गुणों का विकास होता है, जो व्यक्तित्व के संतुलित एवं बहुआयामी विकास में सहायक सिद्ध होते हैं और तनाव मुक्त जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इस अवसर पर विश्वविद्यालय प्रांगण में पारंपरिक एवं नवाचारी खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें ओंकार दौड़, केंद्र कबड्डी, नेताजी की पहचान, मत चूको चौहान, शेर-आदमी-बंदूक और सुदर्शन चक्र प्रमुख रहे। कार्यक्रम में कुलपति प्रो. दयाल सहित कुलसचिव श्री सुनील शर्मा, विभागाध्यक्षों, प्राध्यापकों, विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की।

अटल आरोग्य लैब में 134 प्रकार की जांच निःशुल्क

रायगढ़ जिला चिकित्सालय में 25 हजार 835 जांचें पूरी

शहर सत्ता/रायगढ़/रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की अटल आरोग्य लैब योजना सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में प्रभावी पहल साबित हो रही है। योजना के अंतर्गत किरोड़ीमल जिला चिकित्सालय, रायगढ़ में संचालित अटल आरोग्य लैब से मरीजों को विभिन्न प्रकार की चिकित्सा जांच सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसका लाभ बड़ी संख्या में मरीजों को मिल रहा है। बीते दो माह में 6 हजार 44 मरीजों ने लैब की सुविधा का लाभ उठाया है। इस अवधि में कुल 25 हजार 835 जांचें संपन्न की जा चुकी हैं।

जिला चिकित्सालय स्थित अटल आरोग्य लैब में 134 प्रकार की विभिन्न चिकित्सा जांच की सुविधा उपलब्ध है। इससे मरीजों को आवश्यक जांच के लिए निजी पैथोलॉजी सेंटरों पर निर्भरता कम हुई है। विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए निःशुल्क जांच की यह सुविधा उपचार के साथ-साथ स्वास्थ्य संबंधी खर्च को कम करने में भी मददगार साबित हो रही है।

अटल आरोग्य लैब योजना का उद्देश्य शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों में आधुनिक एवं विश्वसनीय जांच सुविधाओं का विस्तार करना है, ताकि मरीजों को उपचार के लिए आवश्यक जांच उनके जिले में ही उपलब्ध हो सके। इससे ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों से जिला चिकित्सालय पहुंचने वाले मरीजों को भी बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल रहा है। लैब में जांच प्रक्रिया को आधुनिक और सुविधाजनक बनाया गया है। जांच के उपरांत रिपोर्ट डिजिटल माध्यम से मरीजों तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। इससे मरीजों को रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए बार-बार अस्पताल आने की आवश्यकता नहीं पड़ती और चिकित्सकों को भी समय पर जांच रिपोर्ट उपलब्ध होने से उपचार प्रक्रिया में तेजी आती है।

अटल आरोग्य लैब के माध्यम से सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था में जांच सुविधाओं के विस्तार से मरीजों को एक ही स्थान पर आवश्यक जांच, समय पर रिपोर्ट और बेहतर उपचार की सुविधा मिल रही है। निःशुल्क जांच की सुविधा से आर्थिक बचत के साथ मरीजों का समय भी बच रहा है। यह पहल प्रदेश में सुलभ और जन-केंद्रित स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है।

भीड़ नहीं, हौसला ज़रूरी; 5 GEN-Z छात्र-छात्राओं ने उठाई आवाज

तेलीबांधा तालाब पर मैरिटल रेप कानून की मांग को लेकर प्रदर्शन

शहर सत्ता/रायपुर। राजधानी रायपुर के तेलीबांधा तालाब पर GEN-G से जुड़े 5 छात्र-छात्राओं ने मैरिटल रेप कानून बनाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। संख्या भले ही कम थी, लेकिन मुद्दे को लेकर उनकी आवाज और हौसला चर्चा में रहा। प्रदर्शन के दौरान जगदलपुर के गोरखनाथ शर्मा केस का भी जिक्र किया गया। इस मामले में पत्नी की मौत के बाद पति पर गंभीर आरोप लगे थे। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को IPC की धारा 376, 377 और 304 के तहत दोषी ठहराया था। हालांकि, 10 फरवरी 2025 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटते हुए आरोपी को सभी आरोपों से बरी कर दिया। अदालत ने मामले में वैवाहिक संबंधों में IPC की धाराओं के लागू होने और उपलब्ध साक्ष्यों समेत विभिन्न पहलुओं पर विचार किया। GEN-G के इन 5 छात्र-छात्राओं का कहना है कि वैवाहिक रिश्ते में महिला की सहमति और उसके अधिकारों को लेकर कानून में स्पष्टता और सुरक्षा जरूरी है। सिर्फ 5 लोग थे, लेकिन सवाल बड़ा था—क्या वैवाहिक रिश्ते में भी सहमति को कानूनी महत्व मिलना चाहिए?

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक श्री सुकांत राजपूत द्वारा ए.आर. प्रिंटर्स, निरंकारी फर्नीचर के पीछे, पंडरी रायपुर से मुद्रित एवं शहरसत्ता, एस-15 प्रियदर्शिनी नगर, सेक्टर 1, मातृ-पितृ छाया अपार्टमेंट, रायपुर (छ.ग.),
मोबाईल नं. 98271-81979, फोन नं. 0771-3158142, संपादक - सुकांत राजपूत (पीआरबी एक्ट के तहत समाचार के लिए जिम्मेदार), महाप्रबंधक - प्रदीप चंद्रवंशी (मो. 70006-81023)। डाक पंजीयन - CG/RYP/DN/70/2025-27